

## परिवहन मंत्रालय के नए चालान नियमों का कड़ा विरोध: ट्रक ट्रांसपोर्टर्स की आजीविका पर खतरा

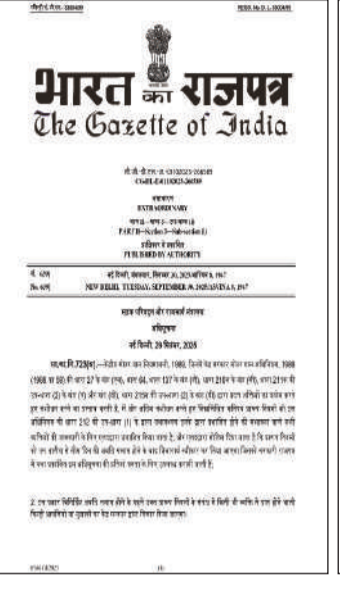
**परिवहन विशेष न्यूज**

नई दिल्ली : उपतत्सा राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजकुमार यादव ने परिवहन मंत्रालय (MoRTH) द्वारा हाल ही में जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि यह नियम ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लाखों ड्राइवरों, ऑपरेटर्स और छोटे व्यवसायियों की आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। यह ड्राफ्ट, जो मोटर व्हीकल रूल्स में संशोधन का प्रस्ताव करता है, चालान प्रक्रिया को अधिक सख्त बनाने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में यह आम आदमी पर अनावश्यक बोझ डालने वाला है। डॉ. यादव ने विभिन्न पहलुओं से इसकी आलोचना करते हुए सरकार से तत्काल पुनर्विचार की मांग की है।

"उपतत्सा" "राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा", (ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी) जो ट्रक ट्रांसपोर्टर्स और सारथी के एकमात्र हितकारी संगठन के रूप में जाना जाता है, देशभर में ट्रांसपोर्ट सेक्टर के हितों की रक्षा करने वाला एक प्रमुख संगठन है। डॉ. यादव ने इस ड्राफ्ट को "ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ एकतरफा हमला" करार दिया और कहा कि यह नियम लागू होने से पहले स्टेकहोल्डर्स से कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया। नीचे विभिन्न पहलुओं से इस विरोध की विस्तृत व्याख्या दी गई है:

**1. आर्थिक प्रभाव: ट्रांसपोर्टर्स पर अनावश्यक बोझ**

ट्रक ट्रांसपोर्ट सेक्टर पहले से ही महंगाई, ईंधन की बढ़ती कीमतों और टोल शुल्कों से जूझ रहा है। नए नियमों के तहत, चालान का भुगतान या चुनौती देने की समयसीमा 45 दिनों तक सीमित कर दी गई है, और अनपेक्षित चालान पर वाहन या लाइसेंस को "Not to be Transacted" फ्लैग कर दिया



जाएगा। इससे RTO में रिन्यूअल या अन्य ट्रांसजेक्शन रुक जाएंगे। डॉ. यादव ने कहा, "ट्रक ड्राइवरों और ऑपरेटर्स को कम आय को देखते हुए, यह नियम उन्हें आर्थिक रूप से पंगु बना देगा। एक छोटा चालान भी अनपेक्षित रूप से वाहन का संचालन रुक सकता है, जिससे रोजगार छिन जाएगा।" संगठन के अनुमान के अनुसार, देशभर में लाखों ट्रक ऑपरेटर्स इससे प्रभावित होंगे, खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों में जहां डिजिटल पहुंच सीमित है।

**2. प्रक्रियागत और व्यावहारिक चुनौतियाँ:**

**डिजिटल विभाजन को बढ़ावा**

ड्राफ्ट में डिजिटल चालान की वैधता केवल 3 दिनों तक और फिजिकल की 15 दिनों तक रखी गई है। साथ ही, हर 15 दिनों में रिमांडर भेजने का

प्रावधान है, लेकिन डॉ. यादव ने इसे अव्यावहारिक बताया। "अधिकांश ट्रक ड्राइवर लंबी दूरी की यात्राओं पर रहते हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट की पहुंच नहीं होती। Vahan और Sarathi पोर्टल पर निर्भरता ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डिवाइड को बढ़ाएगी।" उन्होंने उदाहरण दिया कि राउरकेला जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टर्स पहले से ही सामग्री चोरी और लॉजिस्टिक्स समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऐसे में चालान प्रक्रिया का सख्तीकरण उनकी मुश्किलें दोगुनी कर देगा। चालान कैसिलेशन के लिए कारण रिपोर्ट कराने का प्रावधान अच्छा है, लेकिन यह अधिकारियों के दुरुपयोग को भी आमंत्रित कर सकता है।

**3. कानूनी और अधिकारों का उल्लंघन:**

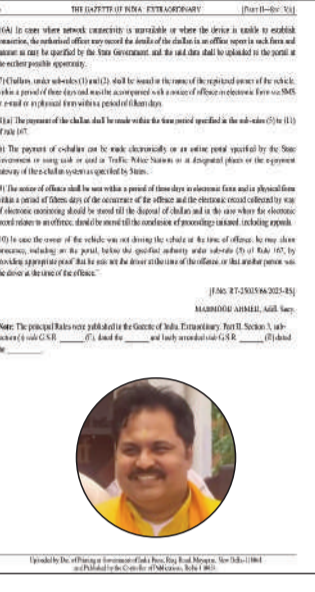
**प्राइवसी और न्याय की अनदेखी**

नियमों में 45 दिनों के बाद चालान को डिफॉल्ट रूप से स्वैच्छिक मान लेना और विवाद की गुंजाइश खत्म करना मौलिक अधिकारों का हनन है। डॉ. यादव ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए कहा, क्या हर व्यक्ति को अपनी सफाई देने का अधिकार नहीं? एक्सीडेंट के मामलों में 3 दिनों के अंदर चालान जारी करने का प्रावधान अनदेखेबल मामलों के लिए समस्या पैदा करेगा। इ संगठन का मानना है कि यह नियम पुलिस और अधिकारियों को अधिक शक्ति देगा, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। साथ ही, यूनिफॉर्म में अधिकृत व्यक्ति द्वारा चालान जारी करने का नियम अच्छा है, लेकिन

ग्रामीण सड़कों पर इसका पालन मुश्किल होगा।

**4. पर्यावरण और सेक्टर-विशिष्ट प्रभाव:**

ट्रांसपोर्ट सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन नए नियम ईंधन मिश्रण (जैसे डीजल में इथेनॉल) जैसी अन्य नीतियों के साथ मिलाकर ड्राइवरों को प्रभावित करेगा। डॉ. यादव ने हाल की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग ईंधन से इंजन डैमेज हो रहा है, जिससे इंधन खर्च बढ़ेगा और रिजेट हो रहे हैं। "चालान नियमों का सख्तीकरण ऐसे समय में आया है जब सेक्टर पहले से संकट में है। यह निर्माण और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में रत-बजरी जैसे अवैध खेलों को रोकने की बजाय वैध ऑपरेटर्स को निशाना बनाएगा।"



## आप सभी की जानकारी हेतु



1 अक्टूबर, 2025 से, आधार कार्ड में सुधार के लिए आधार नामांकन केंद्र पर सुधार के लिए लगने वाले शुल्क का विवरण:

**आधार नामांकन केंद्र पर**

- जनसांख्यिकीय अपडेट (जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के लिए) 75 और
- बायोमेट्रिक अपडेट (उंगलियों के निशान, आँख की पुतली, फोटो) के लिए 125।
- बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय अपडेट की संयुक्त लागत 125.

यह शुल्क आधिकारिक केंद्रों पर अपडेट के लिए है, 4. ऑनलाइन जनसांख्यिकीय अद्यतन के लिए 50 का शुल्क लिया जाता है, तथा ऑनलाइन दस्तावेज अद्यतन निःशुल्क है।

## दिल्ली में पंजीकृत सभी (निजी एवं व्यवसायिक) वाहन मालिकों के लिए जनहित में जारी



**परिवहन विशेष न्यूज**

परिवहन विभाग दिल्ली द्वारा दिल्ली में पंजीकृत सभी वाहन मालिकों के लिए संदेश

प्रिय वाहन मालिक, कृपया वैध पीयूसी प्रमाणपत्र की समाप्ति से पहले अधिकृत पीयूसी केंद्रों से अद्यतन प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) प्राप्त करें। इसका पालन न करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना तथा 3 महीने की अवधि के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की अयोग्यता हो सकती है। अगर आपने पहले ही ऐसा कर लिया है, तो कृपया इसे अनदेखा करें। इस संदेश को दूसरों तक भी पहुंचाएँ और पंजीकृत वाहन मालिकों से वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) प्राप्त करने का आग्रह करें।

-परिवहन विभाग

## टैपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

### मानव अधिकार उल्लंघन की समस्या – वैश्विक परिदृश्य

**पिकी कुंडू :- सदस्य बंगाली प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश शाखा**

**1. राजनीतिक दमन (Political Repression):-** अधिनायकवादी शासन (authoritarian regimes) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और विरोध के अधिकार पर अंकुश। उदाहरण: कई देशों में पत्रकारों, एक्टिविस्टों और विपक्षी नेताओं की हत्या या गिरफ्तारी।

**2. युद्ध और सशस्त्र संघर्ष (Wars & Armed Conflicts):-** \*सीरिया, यमन, गाजा, यूक्रेन जैसे संघर्ष क्षेत्रों में नागरिकों पर हमले।

**3. जातीय और धार्मिक भेदभाव (Ethnic & Religious Persecution)**

- रूम्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार।
- अफ्रीकी देशों में जनसंहार (genocide) जैसी घटनाएँ।
- अल्पसंख्यक समुदायों का दमन।

**4. शरणार्थी और प्रवासी संकट (Refugee & Migration Crisis)**

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2024 तक दुनिया में 11 करोड़ से अधिक विस्थापित लोग (displaced persons) हैं।
- इनमें से लाखों लोग बिना राष्ट्रीयता (stateless) हैं और उनके बुनियादी अधिकार भी नहीं हैं।

**5. आर्थिक और सामाजिक अधिकारों का उल्लंघन**

- बाल श्रम, मानव तस्करी, जबरन मजदूरी।
- स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार का अभाव।
- लैंगिक हिंसा और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव।

**सजा और जवाबदेही की वास्तविक स्थिति**

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) शिकायतों की सुनवाई करती है, लेकिन उसके पास प्रत्यक्ष दंडात्मक शक्ति नहीं है।
- अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और



जनसंहार (genocide) जैसे मामलों में कार्रवाई करता है।

- लैंगिक कई शक्तिशाली देश ICC को मान्यता नहीं देते (जैसे अमेरिका, चीन, रूस)।
- क्षेत्रीय मानवाधिकार निकाय (Regional Mechanisms)**
- यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय (ECHR) – यूरोप में कई सरकारों को सजा और क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए।
- अफ्रीकी और अमेरिकी मानवाधिकार आयोग/न्यायालय – सीमित प्रभाव।
- एशिया में कोई मजबूत क्षेत्रीय मानवाधिकार न्यायालय मौजूद नहीं है।
- राष्ट्रीय स्तर**
- कई देशों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हैं (जैसे भारत का NHRC)।
- लेकिन ये अक्सर "अनुशासा" ही कर पाते हैं, सीधी सजा नहीं दे सकते।

**3. न्यायपालिका की धीमी प्रक्रिया और राजनीतिक दबाव के कारण** दोषियों को बहुत देर से या कभी सजा नहीं मिलती।

**4. वास्तविकता (Ground Reality)**

- अधिकांश मामलों में अपराधी बच निकलते हैं, खासकर जब वे राज्य या सेना से जुड़े हों।
- केवल छोटे या कम शक्तिशाली अपराधियों को ही दंड मिलता है।
- पीड़ितों को न्याय तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं, और कई बार न्याय मिलता ही नहीं।

**कानून बनाम वास्तविकता**

कानून: यूडीएचआर, जिनीवा कन्वेंशन, आईसीसी स्टैच्यू, और कई राष्ट्रीय संविधानों में मानवाधिकारों की सुरक्षा की गारंटी है।

वास्तविकता: राजनीतिक दबाव, शक्तिशाली

**हर हर वाल्मीकि**

समस्त वाल्मीकि समाज एल-ब्लाक शकूरपुर दिल्ली-110034

(स्नेह निमंत्रण)

आश्विन माह पूर्णिमा पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान महर्षि वाल्मीकि जी प्रगत दिवस दिनांक 07 अक्टूबर 2025 को बड़े हंगालास पूर्वक मनाया जा रहा है

इस शुभ अवसर पर आप सादर आमंत्रित हैं

कार्यक्रम में शामिल होकर भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का आशीर्वाद प्राप्त करें।

**\* (कार्यक्रम) \***

**\* पुष्प अर्पित एवं भंडारा \***

दिनांक : 07 अक्टूबर 2025 मंगलवार

समय : दोपहर 2:00 बजे

स्थान : एल-ब्लाक शकूरपुर चौधरी डेयरी के सामने।

निवेदक: समस्त वाल्मीकि समाज एल-ब्लाक शकूरपुर दिल्ली-34

**\* (संचालक) \***

अशोक वैद, दीपक चौहान, राम अवतार पवार

9958532126 / 9212440655 / 9643836191

**"टैपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत" सेवा ही संकल्प है!**

पिकी कुंडू, महासचिव टोलवा ट्रस्ट

हमारा मकसद सिर्फ मदद नहीं, बदलाव लाना है।  
A voice for the voiceless, and a hand for the helpless.

हमारा उद्देश्य है समाज के उन हिस्सों तक पहुंचना जो आज भी भूख, शिक्षा और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। हम जरूरतमंदों को बिना भेदभाव के भोजन, बच्चों को मुक्त शिक्षा, और समाज को जागरूकता देने का कार्य कर रहे हैं।

क्या मिलेगा हमसे जुड़कर  
Ground-level food distribution,  
Getting children free education,  
हम मानते हैं – छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है।  
If you believe in humanity, equality, and service — then you're already a part of our family.  
हमें सपोर्ट करें और एक आवाज बनें इस बदलाव की।  
Together, let's serve. Together, let's change.  
टोलवा ट्रस्ट पंजीकृत से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और फार्म भरकर जुड़ें।

www.tolwa.com/member.html  
स्कैन करे के लिए नीचे दिए गए QR को स्कैन करें और आप टोलवा ट्रस्ट पंजीकृत से फार्म भर कर जुड़ सकते हैं,  
वेब साइट पर www.tolwa.com पर भी जाकर आप फार्म भर के टोलवा ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं। www.tolwa.com

टोलवा ट्रस्ट पंजीकृत  
tolwaindia@gmail.com  
www.tolwa.com

**टैपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)**

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम - डील - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय - 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए - 4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063

कॉर्पोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली 110042



## जीएसटी कम होने से किसको मिला फायदा, जनता को या दूध और दूध निर्मित सामान बनाने और बेचने वालों को

संजय बाटला

भारत सरकार ने जनहित में जीएसटी की नई दर लागू कर जनता में एक विश्वास जगाया पर उसका फायदा क्या मिला जनता को बड़ा सवाल ?

दूध और दूध निर्मित सामानों पर जीएसटी के कम होने से धार्मिक एवं सामाजिक त्योहारों पर जनता को एक अच्छा फायदा होने की आशा जागी थी पर दूध और दूध से निर्मित सामान बनाने वालों ने सरकार को ही टेंगा दिखा दिया और अपने किसी भी प्रोडक्ट की कीमत नहीं घटाई।

दूध, दही, खोया, पनीर, धाप मिठाइयां, घी या अन्य किसी भी प्रोडक्ट का रेट नहीं कम किया गया और इन सभी बातों को देखने के बाद भी चुप है सरकार और विभाग जिनका दायित्व है इस पर नजर रखना और कार्यवाही करना। आखिर क्यों, क्या अमूल, मदर डेयरी या अन्य दूध और दूध से निर्मित



प्रोडक्ट निर्मित करने वालों पर सरकार या विभाग का दबाव डालना संभव नहीं। जनता को जीएसटी की दर कम कर के वाहवाही लूटना ही सिर्फ सरकार का ध्येय था, जनता को उसका फायदा पहुंचाना नहीं।

दूध और दूध से निर्मित सामान बनाने

वालों ने पिछले दो सालों में ही अपने प्रोडक्ट के दामों में 100% से अधिक की वृद्धि कर जनता को खर्चों के बूझ में डाला है और सरकार तब भी चुप रही थी पर अब तो सरकारी राजस्व में आने वाली दर पर सरकार द्वारा ही कटौती की घोषणा की गई है फिर इन सभी के द्वारा

22 तारीख से ही

1. अपने प्रोडक्ट के दामों में कटौती की घोषणा या कटौती क्यों नहीं की, बड़ा सवाल ?  
2. सरकार और विभाग द्वारा अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई, बड़ा सवाल ?

## रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर भीड़ कम करने के प्रति बादली रेलवे स्टेशन, पर कुछ ट्रेनों को हॉल्ट (रोकने) का अनुरोध

संजय बाटला

बादली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव हेतु नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए बादली रेलवे स्टेशन पर कुछ ट्रेनों को रोकने का अनुरोध।

नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए पंजाब की ओर जाने वाली कुछ ट्रेनों को बादली रेलवे स्टेशन पर रोका जाए। इस कदम से न केवल रेल परिचालन की समग्र दक्षता में सुधार होगा, बल्कि यात्रियों के अनुभव में भी सुधार होगा।

अनुरोध के कारण:

- नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर भीड़भाड़ कम करने से देरी कम करने और समय की पाबंदी में सुधार करने में मदद मिलेगी।
- बादली रेलवे स्टेशन यात्रियों के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए एक सुविधाजनक विकल्प के रूप में काम कर सकता है, जिससे मुख्य स्टेशनों पर भार कम हो जाएगा।
- इस कदम से क्षेत्र में रेलवे बुनियादी ढांचे के संतुलित विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।



ठहराव के लिए पात्र ट्रेनें: बादली रेलवे स्टेशन पर रुकने के लिए विचार की जा सकने वाली कुछ ट्रेनें हैं:

- 12450 चंडीगढ़-मडगाँव जं. गोवा संपर्क, क्रांति एक्सप्रेस
- 12484 अमृतसर - कोचुवेली एक्सप्रेस

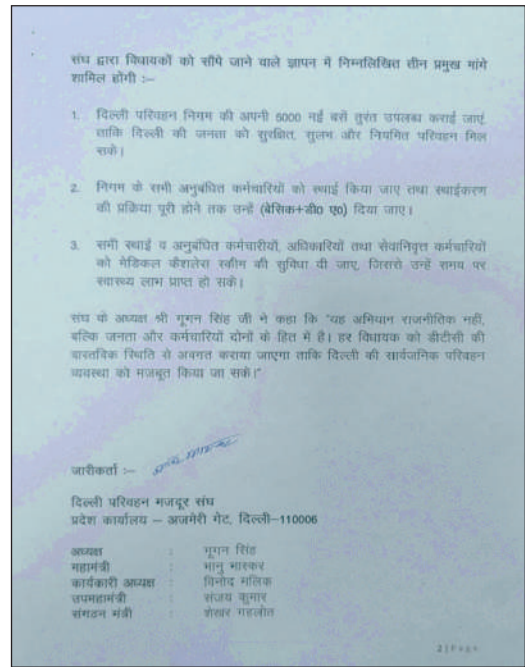
नए ठहराव के लिए मानदंड: रेल मंत्रालय की नीति के अनुसार, नए ठहरावों

पर निम्नलिखित कारणों के आधार पर विचार किया जाता है:

- लागत वसूली: नए ठहराव से 12,716 रुपये से 24,506 रुपये तक की लागत वसूल होगी।
- यात्री यातायात: 500 किमी की दूरी के लिए प्रति ट्रेन प्रति दिन न्यूनतम 40 स्लीपर श्रेणी टिकट या अन्य श्रेणियों में इसके समतुल्य किराया।

3. परिचालन व्यवहार्यता: ठहराव से लाइन क्षमता और ट्रेनों की समयतालिका प्रभावित नहीं होनी चाहिए।  
आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस प्रस्ताव पर विचार करें और बादली रेलवे स्टेशन पर कुछ ट्रेनों के ठहराव के लिए आवश्यक कदम उठाएँ। इससे हजारों यात्रियों को लाभ होगा और समग्र रेल नेटवर्क में सुधार होगा।  
जसपाल सिंह

## दिल्ली परिवहन मजदूर संघ द्वारा "DTC बचाओ अभियान" की शुरुआत



परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन मजदूर संघ ने आज "DTC बचाओ अभियान" की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता दिल्ली की सभी 70 विधानसभा में जाकर 70 विधायक तक पहुंचेंगे और उन्हें (DTC) दिल्ली परिवहन निगम की गंभीर समस्याओं से अवगत कराएंगे।

इस अभियान का उद्देश्य दिल्ली की जनता की जीवन रेखा डीटीसी बस सेवा को सशक्त बनाना, निगम के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना तथा दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करना है।

संघ के महामंत्री श्री भानु भास्कर ने कहा कि "DTC को बचाना दिल्ली की जनता के हित में है। आज जरूरत है कि सरकार निगम को पुनर्जीवित करने के लिए ठोस कदम उठाए और कर्मचारियों की जायज मांगों को स्वीकार करे।"

संघ द्वारा विधायकों को सौंपे जाने वाले विज्ञापन में निम्नलिखित तीन प्रमुख मांगें शामिल होंगी:-

- दिल्ली परिवहन निगम की अपनी 5000 बसें तुरंत उपलब्ध कराई जाए ताकि दिल्ली की जनता को सुरक्षित, सुलभ और नियमित परिवहन मिल सके।
- निगम के सभी अनुबंधित कर्मचारियों को स्थाई किया जाए तथा स्थाईकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें (बेसिक +DA) दिया जाए।
- सभी अनुबंधित कर्मचारियों एवं स्थाई कर्मचारी अधिकारी तथा सेवानिवृत्त



कर्मचारियों को मेडिकल कैशलेस स्कीम की सुविधा दी जाए, जिससे उन्हें समय पर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सके।

संघ के अध्यक्ष श्री गगन सिंह जी ने कहा कि "यह अभियान राजनीति नहीं बल्कि जनता और कर्मचारी दोनों के हित में है। हर विधायक को दिल्ली परिवहन निगम की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाएगा ताकि दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।"

इसकी शुरुआत DTC के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी और मजदूर संघ के कार्यकर्ता विकास कुमार शर्मा ने अपने शह कार्यकर्ताओं को लेकर आज कोकलपुर विधानसभा के विधायक श्री चौधरी सुरेंद्र

कुमार जी को पत्र देकर कहा की अगर कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना गया तो जल्द दिल्ली परिवहन मजदूर संघ बड़े आंदोलन की ओर जाएगा।

दिनांक 07/10/25 को सुबह 9 बजे भारतीय मजदूर संघ के सदस्य DTC कर्मचारियों की समस्या से अवगत कराकर दिल्ली प्रदेश डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट जी को ज्ञापन पत्र दिया जाएगा,

दिल्ली परिवहन मजदूर संघ प्रदेश कार्यालय अजमेरी गेट दिल्ली 110006

- अध्यक्ष: गगन सिंह
- महामंत्री: भानु भास्कर
- कार्यकारी अध्यक्ष: विनोद मलिक
- उप महामंत्री: संजय कुमार
- संगठन मंत्री: शंकर गहलोत

## एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग के नेतृत्व में "आप" पार्षदों ने भाजपा सरकार पर मांगें पूरी करने का बढ़ाया दबाव

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। भाजपा सरकार से समान काम के लिए समान वेतन की मांग कर रहे दिल्ली नगर निगम के एमटीएस कर्मचारियों की हड़ताल में आम आदमी पार्टी के पार्षद भी शामिल हुए और उनकी सभी मांगों का समर्थन किया। नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग के नेतृत्व में हड़ताल में शामिल ए और पार्षदों ने भाजपा सरकार से उनकी सभी मांगें पूरी करने की अपील की। अंकुश नारंग ने कहा कि 8 दिनों से 5 हजार कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उनके हड़ताल पर जाने के बाद से फॉगिंग और टैक चेकिंग बंद है, लेकिन मेयर राज इकबाल सिंह को इसकी कोई चिंता नहीं है। चार इंजन की भाजपा सरकार की विफलता के चलते ही दिल्ली में डेगू, मलेरिया व चिकनगुनिया जैसी महामारिया का शिकार हो रही है। एमसीडी के मलेरिया-डेगू विभाग में तैनात ये कर्मचारी घर-घर जाकर मच्छरों की रोकथाम, फॉगिंग, वाटर टैंक चेकिंग और छिड़काव का काम करते हैं। 25-30 साल से अपनी सेवा दे रहे हैं, फिर भी इनको समान



वेतन नहीं मिल रहा। ये लोग बीमारी के बीच काम करते हैं, लेकिन मेडिकल लीव तक नहीं मिलती। अगर उनकी मौत हो जाती है, तो परिवार को नौकरी का हक नहीं है। इनकी ये मांगें पूरी तरह जायज हैं। आम आदमी पार्टी इनका समर्थन करती है, लेकिन दिल्ली की जनता का नुकसान न हो, इसके लिए तत्काल समाधान चाहिए।

अंकुश नारंग ने कहा कि भाजपा के चारों इंजन फेल हैं। महापौर का अहंकार इतना है कि वे कर्मचारियों की मांगें मानने को तैयार नहीं हैं। आठ दिनों से फॉगिंग, छिड़काव और टैक चेकिंग बंद है।

दिल्ली में डेगू-मलेरिया के मामले पांच साल के उच्चतम स्तर पर हैं, लेकिन भाजपा द्वारा कोई जागरूकता अभियान भी नहीं चलाया जा रहा है। शिक्षा अमीरी-गरीबी नहीं देखती, यह केवल जन्म और हिम्मत की मांग करती है। अंकुश नारंग ने बताया कि मैंने मेडिकल हेल्थ ऑफिसर (एमएचओ) से कर्मचारियों को मिलवाया, जहां आशवासन मिला, लेकिन अमल नहीं हुआ। मैंने

बतौर नेता विपक्ष सदन में भी आवाज उठाई कि हड़ताल से पहले महापौर मिल लें, लेकिन उन्होंने समय नहीं निकाला। कर्मचारी भूख हड़ताल पर हैं। रोज आठ लोगों की टीम 24 घंटे उपवास करती है। महापौर राजा इकबाल सिंह "डमी" मेयर हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा सिर्फ भ्रष्टाचार पर ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रक्षाबंधन पर कर्मचारियों को राखी बंधवाती हैं, लेकिन 5,200 परिवारों को सड़क पर छोड़ दिया।

आम आदमी पार्टी के एमसीडी सह-प्रभारी प्रवीण कुमार ने कहा कि पिछले आठ दिनों से सितिक सेंटर के सामने धरने पर बैठे एमसीडी के मलेरिया-डेगू विभाग के एमटीएस कर्मचारी भारी बारिश, गर्मी और धूप सहते हुए अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन की उनकी मांग पूरी तरह जायज है। उन्होंने कहा कि एमसीडी में एमटीएस कर्मचारियों की सेलरी में भारी असमानता है। किसी की 16,000 रुपये, किसी की 20,000, तो किसी की 26,000 रुपये हैं। कुछ को तो न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही। दुनिया भर में समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू है। ये कर्मचारी घर-घर जाकर डेगू-मलेरिया की रोकथाम के लिए काम करते हैं, फिर भी उनके साथ यह भेदभाव क्यों? उन्होंने कई दौर की बातचीत का जिक्र किया, जो मेयर और एमसीडी अधिकारियों से हो चुकी है, लेकिन भाजपा सरकार इनकी जायज मांगों को मानने को तैयार नहीं है।

## मदरसों में आधुनिक शिक्षा के महत्व पर कौमी तालीमी बेदारी सम्मेलन

तालीमी किट वितरण, महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर

श्रम आगज, नई दिल्ली: पसमांदा विकास फाउंडेशन के तत्वावधान में कौमी तालीमी बेदारी सम्मेलन का आयोजन मदरसा हिफजुल कुरान सैयदान इमाम-ए-हफ्स, पुराना बस स्टैंड, नूह में किया गया। इस सम्मेलन में मदरसों के छात्र-छात्राओं को आधुनिक शिक्षा की अहमियत से अवगत कराया गया और उन्हें "तालीमी किट" वितरित की गई, ताकि वे आधुनिक दौर की शिक्षा के साथ कदम से कदम मिला सकें। फाउंडेशन के निदेशक मेराज राईन ने अपने संबोधन में कहा कि यह तालीमी किट केवल एक किट नहीं, बल्कि आधुनिक शिक्षा से जुड़ने की एक सुविधा है, जिसे हमने "तालीमी जिहाद" का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे धार्मिक शिक्षा आवश्यक है, वैसे ही आधुनिक शिक्षा भी जरूरी है। जब मदरसों के छात्र आधुनिक ज्ञान से परिचित होंगे तो वे केवल अपने समाज ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

मेराज राईन ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ अनेक धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं, इसलिए अन्य भाषाओं का ज्ञान भी जरूरी है ताकि हम एक-दूसरे को बेहतर समझ सकें। उन्होंने यह भी कहा कि

हमें राजनीति से ऊपर उठकर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि सरकारें बदलती हैं, पर व्यवस्था नहीं बदलती। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि समय के साथ खुद को अपडेट करना ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने आगे कहा कि देश में नफ़रत का निशाना हमेशा पसमांदा बनता है, इसलिए शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके ही हम अपनी और देश की तत्काली सुनिश्चित कर सकते हैं। फाउंडेशन की निदेशक निकहत परवीन ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं के बिना संभव नहीं। अगर महिला शिक्षित होगी तो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी शिक्षित होगी। शिक्षा अमीरी-गरीबी नहीं देखती, यह केवल जन्म और हिम्मत की मांग करती है। उन्होंने कहा कि पसमांदा तबके की महिलाओं में शैक्षिक जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है ताकि वे समाज में प्रभावी भूमिका निभा सकें।

कार्यक्रम में नलहड़ मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एम. के. दयाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने पसमांदा विकास फाउंडेशन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि

शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति की सबसे मजबूत नींव है। अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो न केवल उनका भविष्य उज्ज्वल होगा बल्कि पूरे समाज में जागरूकता और सद्भाव का माहौल बनेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी धर्म या वर्ग की संपत्ति नहीं, बल्कि हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। मदरसों के छात्रों को भी आधुनिक वैज्ञानिक और सामाजिक शिक्षा से जोड़ना समय की मांग है। इस अवसर पर पसमांदा विकास फाउंडेशन के संरक्षक कारी असजद चुबैर, अशरफ खान, सैयद फरूख सेर हसीन फातिमा, मुशरफ, समीर उपस्थित रहे। उलेमा टीम के अध्यक्ष मुफ्तूती वसीम अकरम कासमी और मौलाना जाहिद आलम मजाहिरी ने कहा कि इल्म की रौशनी हर दिल तक पहुंचाना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर कमरुद्दीन ने की, जबकि संचालन के फ़र्ज़ मौलाना जाहिद आलम मजाहिरी (अध्यक्ष, टीम उलेमा, पसमांदा विकास फाउंडेशन) ने निभाया। आभार व्यक्त-मौलाना अब्बास नदवी (नाज़िम-ए-तालीमात, मदरसा हिफजुल कुरान सैयदान इमाम-ए-हफ्स, नूह, मेवात) ने किया।

## किफायत की चिंताओं के बावजूद घर की कीमतों में बढ़ोतरी; फेस्टिव सीजन से सकारात्मक माहौल की उम्मीद: हाउसिंग डॉट कॉम और आईएसबी की रिपोर्ट

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली: देश के दूसरे सबसे बड़े रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्र में मांग में नरमी के संकेतों के बावजूद, 13 शहरों के लिए ऑल-इंडिया हाउसिंग प्राइस इंडेक्स (HPI) जून में 14 अंकों की छलांग लगाकर बढ़ गया। आइए इंडिया और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) की रिपोर्ट के अनुसार, इंडेक्स में तिमाही आधार पर भी 8 अंकों की तेज वृद्धि दर्ज की गई, जो कीमतों की रफ्तार को रेखांकित करती है।

यह एचपीआई भारत के प्रमुख डिजिटल रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म हाउसिंग डॉट कॉम (आइए इंडिया के स्वामित्व वाली कंपनी) और आईएसबी की संयुक्त पहल है, जो 13 बड़े शहरों—अहमदाबाद, बंगलुरु, चेन्नई, फरीदाबाद, गांधीनगर, गांधियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नोएडा और पुणे—में आवासीय रुझानों को ट्रैक करती है।

"भारत का हाउसिंग मार्केट 2025 को दूसरी तिमाही में मजबूत रहा, खासकर पॉलिसी के असिस्टेड प्रॉफेसर शंकर तोमर ने बताया कि कीमतों से मिले संकेतों के आधार पर कहा जा सकता है कि जून तिमाही में तुलनात्मक रूप से स्थिरता आई है।" "भारत का हाउसिंग मार्केट 2025 को दूसरी तिमाही में मजबूत रहा, खासकर पॉलिसी के असिस्टेड प्रॉफेसर शंकर तोमर ने बताया कि कीमतों से मिले संकेतों के आधार पर कहा जा सकता है कि जून तिमाही में तुलनात्मक रूप से स्थिरता आई है।"

हाउसिंग डॉट कॉम के सीओओ प्रवीण शर्मा ने कहा, "व्यापारिक अनिश्चितताओं से उत्पन्न अल्पकालिक दबावों के बावजूद, भारत का आवास क्षेत्र परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए आकर्षण और निवेश प्राप्त करता रहेगा। लागत संबंधी चिंताएँ बनी हुई हैं जिन पर सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है, लेकिन कुछ सकारात्मक बदलाव दिखने लगे हैं। उदाहरण के लिए, GST सुधारों से वहीनयता में सुधार होगा, जो खासकर मिड-सेगमेंट में मांग को बढ़ावा देगा—यह श्रेणी भारत के 'सबको घर' के सपने को पूरा करने के लिए सबसे अहम है।" आईएसबी में अर्थशास्त्र और पब्लिक पॉलिसी के असिस्टेड प्रॉफेसर शंकर तोमर ने बताया कि कीमतों से मिले संकेतों के आधार पर कहा जा सकता है कि जून तिमाही में तुलनात्मक रूप से स्थिरता आई है।

और महंगाई पर नियंत्रण को देखते हुए, हमें उम्मीद है कि बड़े घरों की मांग मेट्रो शहरों में आगे भी बाजार को गति देती रहेगी।"

पिछले साल मासिक एचपीआई मूवमेंट (अखिल भारतीय)

क्षेत्रीय मुख्य बिंदु: एनसीआर ने भारत के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले आवास बाजार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, और 2025 की दूसरी तिमाही में 42 अंकों की असाधारण वार्षिक वृद्धि के साथ अग्रणी स्थान पर है। इस क्षेत्र का उत्कृष्ट प्रदर्शन निवेशकों के मजबूत विश्वास, प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत रोजगार सृजन और प्रीमियम आवासीय गलियारों के लिए निरंतर प्रार्थमिकता से उपजा है। 12बीएचके और 32बीएचके दोनों सेगमेंट में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें अधिकांश मांग नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम बाजारों में केंद्रित है।

एक प्रमुख विकास केंद्र के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखते हुए, बंगलुरु ने 24 अंकों की वार्षिक वृद्धि के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। आईटी सेक्टरों की आमद से प्रेरित, इस बाजार ने सभी सेगमेंट में संतुलित वृद्धि दिखाई है, जिसमें प्रीमियम सेगमेंट अग्रणी है। बंगलुरु दक्षिण, आउटर रिंग रोड और अन्य प्रमुख इलाकों जैसे क्षेत्रों ने इस वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

हैदराबाद 20 अंकों की वार्षिक वृद्धि के साथ तीसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला शहर बनकर उभरा, जो शहर के निरंतर विकास पथ को दर्शाता है। ओआरआर वेस्ट, हैदराबाद वेस्ट और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में स्थित इलाकों में, कई सब-मार्केट्स में मजबूत मांग का बाजार को फायदा मिला रहा है।

भारत का सबसे महंगा आवास बाजार होने के बावजूद, एएमएमआर में काफ़ी दिलचस्पी बनी हुई है, जहाँ मांग लगभग और अल्ट्रा-लज्जरी सेगमेंट में केंद्रित है। शहर में जमीन की सीमित उपलब्धता और ऊँची प्रतिस्थापन लागत, कीमतों में बढ़ोतरी को बढ़ावा दे रही है।

कोलकाता में उल्लेखनीय एचपीआई वृद्धि दर्ज की गई, जो मूल्य और बेहतर जीवनशैली सुविधाओं की तलाश करने वाले खरीदारों के बीच शहर के उभरते आकर्षण को दर्शाती है। बाजार स्थानीय सामर्थ्य के अनुरूप कॉम्पैक्ट डिजाइनों को ज्यादा पसंद करता है।

## विकसित भारत के लिए प्रधानमन्त्री खोलें अन्त्योदय श्री विद्यालय

परिवहन विशेष न्यून



नई दिल्ली। महान विचारक और एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर शिक्षक कल्याण फाउंडेशन के तत्वाधान में, शिक्षक सदन, सूरजमल विहार में एकात्म मानववाद से विकसित भारत पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केन्द्रीय राज्यमंत्री माननीय श्री हर्ष मलहोत्रा जी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि यशस्वी प्रधानमन्त्री जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए विशेषकर वंचित समूह के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। शिक्षा के माध्यम वंचित समूह को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार लगातार कार्य कर रही है बजट में शिक्षा के लिए विशेष धनराशि आवंटित की जा रही है।

इस अवसर पर शिक्षक कल्याण फाउंडेशन के संयोजक, भूप्रदुर् उपप्राचार्य श्री जगदीश विग ने मुखर होकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मांग कि वंचित समूह के कारोड़ों बच्चों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए अन्त्योदय श्री विद्यालय पूरे देश में खोले जाएं, जहाँ पर ये बच्चे शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन, परिवार के साथ समाज को विकसित बनायेंगे जिससे कि एकात्म मानववाद से विकसित भारत का सपना साकार हो सकेगा साथ ही रोजगार के नये अवसर पूरे देश भर में सृजित होंगे। परिचर्चा में उपस्थित राजीव साहनी, आईएमए की अध्यक्ष महोदया डॉक्टर श्रीमती शमा वत्रा, अखिल भारतीय शिक्षक संघ के राष्ट्रीय सचिव श्री के पी सिंह, भाजपा नेत्री श्रीमती मंजुला गुप्ता इत्यादि ने परिचर्चा को रोचक और सार्थक बनाया।

### गीतिका छन्द में

**आज ऐसे क्रान्तिकारी चाहिए**

जो स्वयं कर्तव्य पथ की, साधना को साध लें।  
आपदा की आँधियों को, मुहियों में बाँध लें।  
थरथरा उठें कलेजे, नाम सुनकर पाप के।  
शब्द अपने आप उठते, लौट जायें शाप के।।

क्रूर होकर जो अहं को, खूँटियों पर टाँग दें।  
हर प्रहर मुँगे सरीखी, जांगने की बाँध दें।  
जो हृदय इंसानियत के, राग के आगार हो।  
देश पर हर हाल भिटने, के लिए तैयार हो।

वे पुरुष हों या कि नारी, चाहिए इस देश को।  
आज ऐसे क्रान्तिकारी, चाहिए इस देश को।।

दूसरों के यूँ न ताकें, साथियों को साथ दें।  
जो गिरे उनको उठा लें, हाथ को निज हाथ दें।  
भारती मी की न निन्दा, भूलकर भी सह सकें।  
देख कर बेदेन धरती, खुद न जिन्दा रह सकें।

प्रेम को पूजा समझ कर, धर्म को आधार दें।  
जो हृदय की बीथियों में, खीम सा विस्तार दें।  
क्या प्रणा क्या द्वेष-ईर्ष्या, लोभ-लालच क्या भला!  
पर जिसे चालाकियों को, परखने की हो कला।।

नीति के पकड़े पुजारी, चाहिए इस देश को।  
आज ऐसे क्रान्तिकार, चाहिए इस देश को।।

## आशिक भाई देवासवाला की पहली पुस्तक का विमोचन हुआ

इन्दौर में आशिक हुसैन देवासवाला के पहले लघुकथा संग्रह का साक्षी बनना अपने आप में गर्वोक्ति पूर्ण है क्योंकि, मूर्धन्य विरिष्ठ साहित्यकारों से सजे मंच ने अपनी गरिमा को उन्चासन पर विराजमान करवाया था। यह कहने में जरा भी संशय नहीं है कि यह सारस्वत आयोजन साहित्यिक कुंभ से कम भी नहीं था। हर पक्ष आत्मीयता की पृष्ठभूमि की पटकथा से आधारभूत रहा। यकीनन श्री आशिक हुसैन देवासवाला की लघुकथाएं मानवीय संवेदनाओं से संवाद करती हैं। ऐसा दृश्य पहली बार दृश्य हुआ जब वयोवृद्ध मातृश्री के हाथों में अपने विक्करील बेटे को लेखनी भी आशीष पा रही थी। इस आयोजन में विरिष्ठ व्यंग्यकार यशवंत गोरे, लघुकथा के अदुभूत चित्तेर कहे जाने वाले विरिष्ठ साहित्य मनीषी श्री योगेंद्रनाथ शुक्ल, देश ही नहीं विदेश में भी कई कृतियों से सुविख्यात छवि अंकित करने वाली की साहित्यकार श्रीमती ज्योति जैन, समाजसेवी शिक्षाविद् श्री जुजर भाई मंच को अपनी बोद्धिक दियता से आलोकित कर रहे थे। इस साहित्य संगम में गोते लगाने के लिए हम आदरणीय श्री देवेन्द्र जी शर्मा, श्री दिनेश तिवारी, श्री दिनेश गंगराडे , भीपाल का प्रतिनिधित्व स्वरूप श्री वसंत बापट, डॉ. मनोष देव, विरिष्ठ लेखिका श्रीमती कुसुम जैन, श्रीमती शोला चंदन, श्री बुरहानुद्दीन शकरवाला , श्री हरिहरसिंह चौहान, श्री संजय सराणेकर, श्री मुफज्जल हुसैन, श्री आरिफ हुसैन हाटपीपल्या, श्री साजिद अली सहित बड़ी संख्या साहित्यानुरागी मौजूद थे। इन सबके बीच इस आयोजन के एक-एक पल और दृश्य को कैमरों में कैद करने वाले विरिष्ठ पत्रकार-फोटो जर्नालिस्ट श्री निशिकांत मंडलोई की उपस्थिति सराहनीय रही। कार्यक्रम का संचालन विरिष्ठ पत्रकार अनिल कुमार धडवईवाले ने किया। हरिहरसिंह चौहान इन्दौर



# कफ सिरप विवाद-सर्दी खांसी की दवा से पैदा हुआ राष्ट्रीय अलार्म और अंतरराष्ट्रीय चिंता- स्वास्थ्य सुरक्षा, नियमन और जवाबदेही पर व्यापक विश्लेषण

**एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गौदिया महाराष्ट्र**

भारत में पिछले कुछ समय से दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में एक कफ सिरप को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, उसने न केवल भारत के कई राज्यों को कारंवाई के लिए मजबूर किया है, बल्कि यह मामला अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय भी बन गया है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राजस्थान और केरल जैसे राज्यों ने इस सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि गुजरात समेत कई अन्य राज्यों ने इसके जारी के आदेश दिए हैं। एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गौदिया महाराष्ट्र यह मानता हैं कि यह पूरा प्रकरण भारत के औषधि नियंत्रण ढांचे, दवा उद्योग की पारदर्शिता, और बच्चों की सेहत से जुड़े गंभीर सवाल खड़े करता है। इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, कफ सिरप विवाद- खांसी की दवा से पैदा हुआ राष्ट्रीय अलार्म और अंतरराष्ट्रीय चिंता- स्वास्थ्य सुरक्षा, नियमन और जवाबदेही पर व्यापक विश्लेषण।

साथियों बात अगर हम एक कफ सिरप विवाद की पृष्ठभूमि, प्रतिबंध तथा कफ सिरप खांसी की दवा से कैसे मचाहाहाकार इसको समझने की करें तो एक कफ सिरप एक ओवर- द-काउंटर (ओटीसी) दवा के रूप में बाजार में बेची जा रही थी। यह सामान्य तौर पर सर्दी, खांसी और जुकाम से राहत के लिए दी जाती थी। इस सिरप का निर्माण कई छोटी फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा किया जा रहा था, और

वे इस सिरप के सभी बच्चों को बाजार से वापस लें और जांच रिपोर्ट आने तक इसकी बिक्री बंद रखें। (3) महाराष्ट्र सरकार ने इसी दिशा में कदम उठाते हुए सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स को नोटिस जारी किया कि वे इस सिरप को अपने स्टॉक से हटा दें। (4) केरल ने भी इसके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और केंद्र से यह स्पष्ट करने की मांग की कि आखिर इस दवा को ड्रग कंट्रोल ऑथॉरिटी की मंजूरी कैसे मिली। (5) गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों ने जांच शुरू कर दी है कि कहीं बाजार में बिक रही अन्य कफ सिरप में भी ऐसे ही हानिकारक तत्व तो नहीं हैं।

स्वास्थ्य विभागों को रिपोर्ट मिली कि बच्चों को यह सिरप देने के बाद उल्टी, सांस लेने में तकलीफ और लिंवर फेल्योर जैसी लक्षण सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के बाद महाराष्ट्र एफडीए ने कोलेंड्रिफ सिरप (बैच एसआर-13) की बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी है। (यूपी) ड्रग्स विभाग ने मेडिकल स्टोर में रखे गए कफ सिरप के जांच के आदेश दिए हैं, इस सिरप से अब तक एमपी में 16 और राजस्थान में 3 बच्चों की मौत होने की जानकारी मीडिया में आ रही है, इसके बाद जब ड्रग्स शाखा में जांच की गई, तो पाया गया कि इस दवा में प्रोपॉप्रॉथोलिन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल जैसे अत्यंत जहरीले रासायनिक तत्व मौजूद हैं। इन दोनों रसायनों का उपयोग सामान्यतः एंटीबैक्जि के रूप में औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है, और इनका मानव शरीर में प्रवेश घातक साबित होसकता है। यही वह बिंदु था जिसने उस कफ सिरप को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवाद के केंद्र में ला दिया किन राज्यों ने इसी कारंवाई- तमिलनाडु से केरल तक बैंन की लहर- इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कई राज्यों ने तुरंत कदम उठाए। (1) तमिलनाडु सरकार ने सबसे पहले इस सिरप की बिक्री और वितरण पर रोक लगाने की घोषणा की। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बच्चों में विषाक्तता के कुछ मामलों देखने के बाद पहिलियती कदम उठाना जरूरी था। (2) मध्य प्रदेश ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) को आदेश दिए कि

गिरेन्द्रसिंह भदौरिया प्राण इन्दौर म.प्र. 919424044284

स्वामी ज्ञानानंद महाराज के नेतृत्व में असंख्य भक्तों-श्रद्धालुओं ने की श्रीधाम वृन्दावन की पंचकोसी परिक्रमा

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

वृन्दावन। परिक्रमा मार्ग स्थित श्रीकृष्ण कृपा धाम में चल रहे त्रिदिवसीय दिव्य व भव्य शरदोत्सव के तीसरे दिन देश-विदेश से आए असंख्य भक्तों-श्रद्धालुओं ने महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज के नेतृत्व में श्रीहरिनाम संकीर्तन के मध्य श्रीधाम वृन्दावन की पंचकोसी परिक्रमा की। तत्पश्चात श्रीहरिनाम महाराज मण्डल, वृन्दावन के द्वारा संगीतमय सुन्दरकाण्ड का सामूहिक पाठ किया गया। इस अवसर पर महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने भक्तों-श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि शरद पूर्णिमा ऋतु परिवर्तन से जुड़ा एक मनोहारी व पुरातन लोक पर्व है। यह धार्मिक पर्व होने के साथ-साथ स्वास्थ्य संवर्धन का भी पर्व है। क्योंकि इस दिन चंद्रमा से जो अमृततुल्य किरणें ज्योत्सना के माध्यम से पृथ्वी को जन्म हुआ था। यह औषधि तुल्य हुआ करती है। भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवद्गीता में भी यह स्पष्ट रूप से कहा है कि र में ही इस स्वरूप अमृतमय चंद्रमा होकर सम्पूर्ण औषधियों व वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। र भगवान श्रीकृष्ण का यह कथन शरद पूर्णिमा की उपायवधियों को सिद्ध करता है। विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में चंद्रमा को र औषधीशर अर्थात् औषधियों का स्वामी कहा गया है। स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि शरद पूर्णिमा के ही दिन भक्ति की पराकाष्ठा मानी जाने वाली श्रीकृष्ण समर्पित मीरा बाई का जन्म हुआ था। आज ही के दिन र गोपी गीतर का उद्भव हुआ था। इसके अलावा देवी पार्वती व आदिदेव महादेव के पुत्र कार्तिकेय का जन्म भी शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। शरद पूर्णिमा श्रीराम कथा के आदि सर्जक महर्षि वाल्मीकि का अवतरण दिवस भी है। इस

द्वन्दावन। चैतन्य विहार फेस-2 स्थित मुरली निकुंज में श्री मुरली निकुंज निष्काम सेवा संस्थान के द्वारा टाकुरश्री मुरली बिहारी सरकार का 12वां पाटोत्सव विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मध्य अत्यंत श्रद्धा एवं धूमधाम के साथ संपन्न हुआ जिसके अंतर्गत टाकुरश्री मुरली बिहारी सरकार का पंचामृत से अभिषेक कर वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य पूजन-अर्चन किया गया। साथ ही उन्हें 56 भोग निवेदित किए गए। तत्पश्चात आयोजित सन्त-विद्वत् संगोष्ठी में पुराणाचार्य डॉ. मनोज मोहन शास्त्री एवं राष्ट्रीय सन्त राधे राधे बाबूजी महाराज ने कहा कि शरद पूर्णिमा शीत ऋतु का अत्यंत पावन व उद्वोधक पर्व है। आज के ही दिन भगवान श्रीकृष्ण ने असंख्य ब्रज गोपीकाओं के साथ महारास लीला की थी जिसके दर्शन करने के लिए तमाम देवता आकाश पर छाए रहे थे। हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे दिव्य पर्व पर आज से 11 वर्ष पूर्व हम सभी के अत्यंत प्रिय आचार्य राजेन्द्र महाराज ने मुरली निकुंज की स्थापना कर उसमें टाकुरश्री मुरली बिहारी सरकार विराजित किया था जिसका उद्घाटन पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने किया था। प्रख्यात भागवताचार्य डॉ. अशोक शास्त्री एवं कार्ष्णि नागेन्द्र महाराज ने कहा कि भागवत मनीषी स्वामी डॉक्टर शिवकरणा पांडेय महाराज के परमकृपापात्र शिष्य आचार्य राजेन्द्र

अग्रणीय है। इसके समस्त सेवा कार्य अति प्रशंसनीय हैं। इस अवसर पर मथुरा-वृन्दावन नगर निगम के उपसभापति मुकेश सारस्वत, क्रान्तिकारी सन्त स्वामी सत्यमित्रानंद महाराज, श्रीराम कथा मर्मज्ञ अशोक व्यास महाराज, आचार्य विपिन बापू, श्याम सुन्दर ब्रजवासी, वैष्णवाचार्य देवाशु गोस्वामी, आचार्य धर्मेन्द्र महाराज (वीतीबरा पीठ), धर्मवीर शास्त्री, रासाचार्य स्वामी रामशरण शर्मा, स्वामी प्रेम शरण शर्मा, आचार्य जुगल किशोर शास्त्री, डॉ. राधाकांत शर्मा, भजन गायक विष्णु वावरा, हरिवंश, आचार्य रवींद्र शास्त्री, ब्रजराज अनिरुद्धाचार्य महाराज, प्रमुख समाजसेवी चंचल कालिया (दिल्ली), मीनाक्षी गर्ग, सुलोचना बंसल, सुभाष गोयल, मीनाक्षी सिंगला, विनोद गर्ग, प्रिय गोयल, ब्रजराज सिंह, आचार्य धर्मेन्द्र त्रिवेदी आदि के अलावा देश के विभिन्न प्रांतों से आए सैकड़ों भक्तों-श्रद्धालुओं की उपस्थिति विशेष रही। संचालन आचार्य रामविलास चतुर्वेदी ने किया। मुरली निकुंज आश्रम के संस्थापक आचार्य राजेन्द्र महाराज ने महोत्सव में पधारे समस्त सन्तों, विद्वानों व धर्माचार्यों को उत्तरीय ओढ़ाकर एवं टाकुरजी का पुटका-प्रसादी-माला आदि भेंट करके सम्मानित किया। महोत्सव का समापन सन्त ब्रजवासी वैष्णव सेवा एवं वृहद भंडारे के साथ हुआ। जिसमें सैकड़ों व्यक्तियों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया।



“यूपी रत्न” डॉ. गोपाल चतुर्वेदी एवं भागवताचार्य आचार्य सुरेशचंद्र शास्त्री ने कहा कि आचार्य राजेन्द्र महाराज के द्वारा संस्थापित श्री मुरली निकुंज निष्काम सेवा संस्थान धर्म व अध्यात्म के अलावा समाजसेवा के क्षेत्र में भी



## गाड़ी भगने पर कानपुर में छात्र को अधमरा करने वाला चौकीइंचार्ज लाइन हाजिर

कानपुर। अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही तथा जनता की सेवा और सहायता के उद्देश्य से गठित पुलिस विभाग के लोग अक्सर अमानवीय व्यवहार करने से भी बाज नहीं आते। ऐसी ही एक घटना में एक चौकी इंचार्ज ने गाड़ी भगाने पर छात्र को अधमरा कर दिया। जिसके बाद उसे लाइन हाजिर करके मामले की जांच एसीपी बाबू पुरवा को दी गई है।

जानकारी के मुताबिक किदवाई नगर में ओवर स्पीड के आरोप में पकड़े गए छात्र महेश के मारपीट न करने का नियम बताते पर भड़के चौकी प्रभारी ने थपड़ों की बौछार करते हुए उसे लातें भी मारी। इतना दुरुस्त कर देने की धमकी देने का वीडियो बनाकर उसके एक साथी ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो भी प्रचलित कर दिया, जिसे संज्ञान में लेकर डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच बाबू पुरवा के एसीपी को दी गई है।

याद रहे कि यह मामला पहला नहीं है। इसके पहले भी पुलिस पर इसी तरह के कई आरोप लगा चुके हैं। इस तरह की घटनाओं में कई पुलिस वालों का स्पेड भी किया जा चुका है लेकिन इसके बाद भी पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार की घटनाएं रकने का नाम नहीं ले रही है। मतलब कोई न कोई आप दिन उनके अमानवीय व्यवहार का शिकार हो रहा है।

कई जगह माता-पिता ने घरों में रखी सभी कफ सिरप की बोटल फेंक दीं। मेडिकल दुकानों ने बिक्री बंद कर दी। डॉक्टरों के पास बड़ी संख्या में लोग यह पूछने पहुंचे कि कौन सी खांसी की दवा सुरक्षित है। यह परिदृश्य बताता है कि भारत में स्वास्थ्य संचार (हेल्थ विषाक्तता किडनी फेल्योर, दृष्टि हानि, सांस लेने में रुकावट और अंततः मृत्यु तक का कारण बन सकती है।) भारत में यह कोई पहली घटना नहीं है, 1998 में दिल्ली में, और 2020 में जम्मू-कश्मीर में भी डॉईजी विषाक्तता से बच्चों की मौतें हो चुकी हैं। साथियों बात अगर हम दवा नियामक प्रणाली पर सवाल, जांच, जिम्मेदारी और जवाबदेही को समझने की करें तो, कफ सिरप प्रकरण ने भारत की ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रभाव डाल दिया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनरेरिक दवा निर्माता है और 200 से अधिक देशों को दवाएँ निर्यात करता है। ऐसे में बार-बार भारतीय

दृष्टिकोण, विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैश्विक नियामक एजेंसियों की भूमिका को समझने की करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के दवा नियामक निकायों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा यूएस एफडीए यूके, एमएचआरए और यूरोपीय औषधि एजेंसी जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों का भारत में बने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर नजर रखे हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने बयान में कहा, “बच्चों की दवाओं में कोई भी ग्लाइकोल बेस्ड टॉक्सिन की मौजूदगी वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है।” इस मामले का असर भारत की फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट ईंडस्ट्री पर भी पड़ सकता है, विदेशी खरीदार भारतीय दवाओं की क्वालिटी सर्टिफिकेशन को लेकर ज्यादा सतर्कता बरतने लगे हैं, जिससे भारत की दवा कंपनियों की विश्वसनीयता और बाजार हिस्सेदारी पर असर पड़ सकता है। साथियों बात अगर हम कानूनी और प्रशासनिक कार्यवाही तथा क्या दोषियों को सजा मिलेगी? को समझने की करें तो, स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने इस मामले की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की है। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित निर्माताओं, डिस्ट्रीब्यूटर्स और डॉलरों के खिलाफ कार्रवाई करें। अगर जांच में यह सिद्ध होता है कि इन कंपनियों ने जानबूझकर या लापरवाही से खतरनाक तत्वों का प्रयोग किया है, तो ड्रग्स एंड कॉन्ट्रोल एक्ट्स 1940 के तहत उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माना का प्रावधान है।

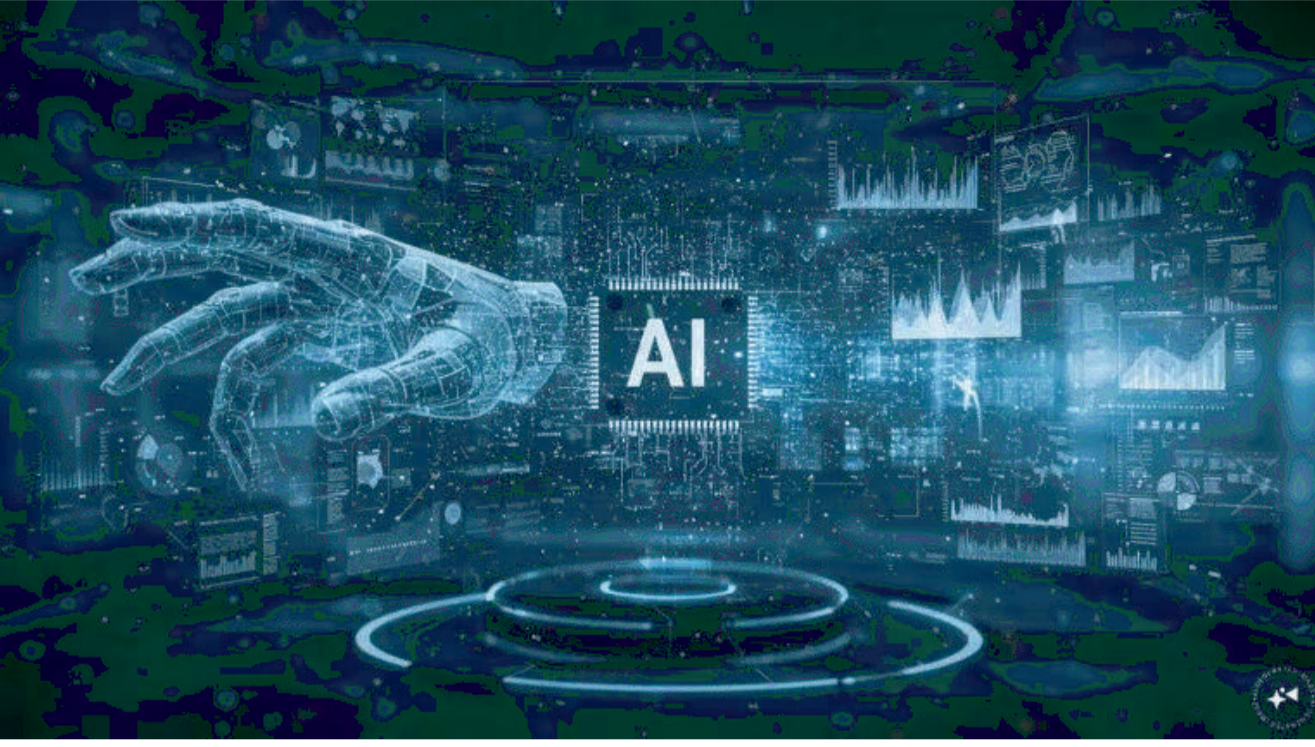


# ऐआई के युग में रॉक-सॉलिड एसटीईएम फाउंडेशनल कौशल का निर्माण



विजय गर्ग

यह व्यापक रूप से माना जाता है कि स्वचालन ने कई पारंपरिक एसटीईएम भूमिकाओं को अनावश्यक बना दिया है, जबकि अन्य लोग अभिजात वर्ग कंपनियों में भी तकनीकी बर्खास्तियों की ओर इशारा करते हैं। एक आईटी कंपनी द्वारा कोडर्स के लिए 450 नौकरियों की भर्ती का हालिया अनुभव यह दर्शाता है कि हमें मूल कौशल पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता क्यों है। 450 नौकरियों के लिए 12,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया। दुर्भाग्यवश, किसी भी उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जा सका क्योंकि उनमें से अधिकांश व्यवसाय की समस्या का समाधान करने के बजाय कोड के लिए एआई टूल पर भरोसा करते थे।



एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) कौशल का महत्व। इस ऐआई युग में तोस एसटीईएम बुनियादी कौशल बनाना महत्वपूर्ण है। भारत में एसटीईएम प्रथाओं ने एक अजीब विरोधाभास देखा है। राज्य स्तरीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एसटीईएम शिक्षकों के लिए निराशाजनक प्रवेश ने एक असहज प्रश्न उठाया है - क्या गिरावट एसटीईएम शिक्षा में बढ़ती आत्मविश्वास की कमी का प्रतिबिंब है? एक ओर, हम एसटीईएम स्नातकों की बड़ी संख्या में उभरते हुए प्रवृत्ति के गवाह हैं; दूसरी ओर, बुनियादी इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक क्षेत्रों में बेरोजगारी और असुविधा के बारे में चिंताएं हैं। भारत कौशल रिपोर्ट (2024) के हालिया आंकड़ों में बताया गया है कि केवल 50% भारतीय स्नातक ही रोजगार योग्य माने जाते हैं। एसटीईएम माइंड्स (अब एसएचएल) की एक रिपोर्ट में पाया गया है कि भारतीय इंजीनियरिंग स्नातक कई चुनौतियों के कारण ज्ञान अर्थव्यवस्था में बेरोजगार हैं - व्यावहारिक संपर्क का अभाव, कम संचार कौशल और अप्रचलित पाठ्यक्रम। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि स्वचालन ने कई पारंपरिक एसटीईएम भूमिकाओं को अनावश्यक बना दिया है, जबकि अन्य लोग अभिजात वर्ग कंपनियों में भी तकनीकी बर्खास्तियों की ओर इशारा करते हैं। एक आईटी कंपनी द्वारा कोडर्स के लिए 450 नौकरियों की भर्ती का हालिया अनुभव यह दर्शाता है कि हमें मूल कौशल पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता क्यों है। 450 नौकरियों के लिए 12,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया। दुर्भाग्यवश, किसी भी उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जा सका क्योंकि उनमें से अधिकांश व्यवसाय की समस्या का समाधान करने के बजाय कोड के लिए एआई टूल पर भरोसा करते थे। कई छात्र त्वरित सुधार करने के लिए प्रलोभित होते हैं जिन्हें एसटीईएम में टोस आधार हल कर सकता है।

एसटीईएम मूलतः प्रणालियों को समझने के बारे में है। ये जैविक, भौतिक, सूचनात्मक या यहां तक कि मैकेनिकल भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एसटीईएम की समझ एक छात्र को तैयार उत्तरों के बजाय चैटजीपीटी पर अधिक शोध करने में सक्षम बना सकती है। स्वाभाविक रूप से, एसटीईएम वास्तविक मूल नवाचार का आधार है। डेमिस हसाबिस को देखो। उनके पास संज्ञानात्मक तंत्रिका विज्ञान में पीएचडी है, लेकिन यह उनकी वैज्ञानिक समझ है जो उन्हें अल्फागोल्ड परियोजना में डेटा का उपयोग करने की अनुमति देती है। उस परियोजना ने प्रोटीन फोल्डिंग की जटिल समस्या को हल किया। यह न केवल एआई समुदाय के लिए एक उपलब्धि थी बल्कि जीवविज्ञान, भौतिकी और मशीन लर्निंग को जोड़ने वाले पूरे अंतर-अनुशासनात्मक विज्ञान का भी। भारत में भी, इसरो का चंद्रयान-3 मिशन केवल कच्चे कोडिंग प्रतिभा का उत्पाद नहीं था। इसमें सटीक इंजीनियरिंग, कक्षा यांत्रिकी, सामग्री विज्ञान और लागू गणित की आवश्यकता थी। ये अपने शास्त्रीय रूप में एसटीईएम डोमेन हैं। एसटीईएम कौशल के साथ वास्तविक समस्या यह है कि शिक्षाएं अलग-अलग लग सकती हैं - आवेदन से दूर। एक अच्छा समाधान एसटीईएम शिक्षा को सिस्टम शिक्षा के रूप में पुनः कल्पना करना होगा। एक जो मजबूत उद्योग इंटरफ़ेस, आधुनिक प्रयोगशाला पहुंच और अंतःविषय परियोजनाओं पर केंद्रित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप, सक्रिय शिक्षण का विचार कक्षा में सीखने को पुनः परिभाषित करने के लिए प्रौद्योगिकी, मानव बातचीत और यहां तक कि अंतर-अनुशासनात्मक दृष्टिकोणों पर भी कटौती करता है। एआई की वृद्धि ने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और बर्खास्तगी के बारे में भय पैदा किया है। हालांकि ऐसा डर

गलत स्थान पर नहीं है, लेकिन यह पूरी तस्वीर को नजरअंदाज कर देता है। एक व्यवहार्य एआई मॉडल वास्तव में उन लोगों के लिए मूल्य बढ़ा सकता है जो ऐसी प्रणालियों के पीछे विज्ञान और कला को समझते हैं। उदाहरण के लिए, जेनेरेटिव एआई कोड लिख सकता है, लेकिन क्या हम इसे मानव पर्यवेक्षण के बिना एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में जटिल सिमुलेशन को मान्य कर सकते हैं? शायद नहीं। ये ऐसे पहलू हैं जिन्हें अभी भी मानवीय भागीदारी की आवश्यकता है। जैसे डेमिस हसाबिस, डॉ. स्टैनफोर्ड में फेई-फेई ली या प्रतिष्ठित संस्थानों के कई भारतीय एआई शोधकर्ताओं का तर्क है कि एसटीईएम शिक्षा एआई आउटपुट पर सवाल उठाने और आगे सुधार करने के लिए आवश्यक बुनियादी ज्ञान प्रणाली है। एसटीईएम शिक्षा जलवायु मॉडलिंग, अंतरिक्ष अनुसंधान, जैव चिकित्सा विज्ञान और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है जहां गलतियों के वास्तविक दुनिया के परिणाम होते हैं। एआई एक गुणक है, प्रतिस्थापन नहीं। यह मांग रूट कोडिंग से दूर रहेगी और एल्गोरिदम डिजाइन, गणितीय मॉडलिंग और सिस्टम एकीकरण को आगे जाएगा। एसटीईएम या शिक्षा को वास्तव में नौकरी के मार्ग के रूप में देखा गया है। लेकिन एक अच्छा बुनियादी आधार बढ़ते झूठे विज्ञान, गलत सूचना और यहां तक कि वैचारिक चरमपंथ के खिलाफ देश का बचाव है। यदि सही ढंग से वितरित किया जाए तो एसटीईएम जांच, झूठपान और साक्ष्य की संस्कृति पैदा कर सकता है। ये एक समाज में खुद को तोड़ने के बिना आधुनिकीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में, अटल नवाचार मिशन या राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन जैसी सफल पहलुओं की संभावना बहुत अधिक है, यदि एसटीईएम पाठ्यक्रम मजबूत बनी रहे। सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, शैक्षिक स्तंभकार, प्रख्यात शिक्षाविद्, गली कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब



## कौशल-आधारित मूल्यांकन गणित शिक्षा का भविष्य क्यों है

विजय गर्ग

आज की तेजी से बदलती दुनिया में गणित सिखाने और मूल्यांकन करने के पारंपरिक तरीके अब पर्याप्त नहीं हैं। ध्यान स्मृति और यांत्रिक समस्या-समाधान से गहरी समझ, तर्क और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग को विकसित करने की ओर जा रहा है। यह बदलाव कौशल-आधारित मूल्यांकन (सीबीए) में शामिल है - एक शैक्षिक दृष्टिकोण जो मापता है कि छात्र वास्तव में क्या कर सकते हैं।

### मूल सीखने से लेकर वास्तविक समझ तक

दशकों से गणित के मूल्यांकन में समझ पर तेजी और सटीकता पर जोर दिया गया है। छात्र अक्सर अपने पीछे की अवधारणाओं को सही ढंग से समझने के बिना सूत्रों को याद करते हैं। हालांकि, योग्यता आधारित मूल्यांकन इस फोकस को बदल देता है। यह शिक्षार्थियों को आवेदन के माध्यम से अपनी विशेषज्ञता प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करता है - अपरिचित समस्याओं का समाधान, तार्किक तर्क और उनकी सोच की व्याख्या।

### प्रत्येक छात्र के लिए व्यक्तिगत शिक्षा

कौशल-आधारित मूल्यांकन की सबसे बड़ी ताकतों में से एक वैयक्तिकरण है। एक आकार की सभी परीक्षाओं के विपरीत, सीबीए छात्रों को अपनी गति से प्रगति करने की अनुमति देते हैं। एक छात्र जो बीजगणित में तेजी से माहिर होता है, वह आगे बढ़ सकता है, जबकि कोई अन्य व्यक्ति जो अंशों के साथ संघर्ष करता है, उसे तब तक लक्षित सहायता मिलती है जब तक कि वे योग्यता प्रदर्शित न कर लें। यह मॉडल आत्मविश्वास, जिज्ञासा और विकास की मानसिकता को बढ़ावा देता है।

### वास्तविक दुनिया के लिए छात्रों की तैयारी

वास्तविक दुनिया में गणित में शायद ही कभी चार विकल्पों से सही उत्तर चुनना शामिल होता है। इंजीनियर, डेटा वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री जटिल, खुला अंत वाली समस्याओं का समाधान करते हैं जिन्हें रचनात्मकता और तर्क की आवश्यकता होती है। योग्यता-आधारित मूल्यांकन इस वास्तविकता को दर्शाता है - छात्र प्रामाणिक संदर्भों में गणित लागू करते हैं, डेटा की व्याख्या करते हैं और अपनी पसंद का समर्थन करते हैं। ये डेटा-आधारित और एआई संचालित दुनिया में आवश्यक कौशल हैं।

### बेहतर प्रतिक्रिया, बेहतर सीखना

पारंपरिक मूल्यांकन अक्सर एक ग्रेड के साथ समाप्त होते हैं, जिससे चिंतन करने को बहुत कम जगह होती है। इसके विपरीत, सीबीए शैक्षिक प्रतिक्रिया पर जोर देते हैं - छात्रों को यह बताने के लिए कि उन्होंने क्या अच्छा किया, कहां गलत

हुआ और वे कैसे बेहतर हो सकते हैं। शिक्षक और शिक्षकों के बीच यह निरंतर संवाद न केवल सीखने का एक उपकरण बनाता है।

### शिक्षकों और प्रणालियों को सशक्त बनाना

योग्यता आधारित मॉडल शिक्षकों को भी सशक्त बनाते हैं। वे शिक्षकों को परीक्षा स्कोर के बजाय कौशल प्रगति और अवधारणात्मक गहराई पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं। स्कूल वास्तविक समय में प्रत्येक छात्र को ताकतों और अंतराल को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे अधिक प्रभावी हस्तक्षेप और निष्पक्ष परिणाम मिलते हैं।

### आगे की सड़क

चूंकि दुनिया भर की शिक्षा प्रणालियों में डिजिटल उपकरण, अनुकूलनात्मक सीखने के प्लेटफॉर्म और एआई-चालित विश्लेषण शामिल हैं, इसलिए योग्यता आधारित मूल्यांकन स्वाभाविक रूप से सीखने के भविष्य में फिट बैठता है। यह भारत में पीआईएसए और एनईपी 2020 जैसे वैश्विक मानकों के अनुरूप है - महत्वपूर्ण सोच, आवेदन और आजीवन शिक्षा कौशल को बढ़ावा देना। बेहतर प्रतिक्रिया और स्पष्टता प्रदान करता है।

व्यापक प्रतिक्रिया: शिक्षक विशिष्ट क्षमताओं से सीधे जुड़े समय पर, प्रासंगिक और विस्तृत फीडबैक प्रदान कर सकते हैं, जिससे छात्रों और माता-पिता को यह अधिक स्पष्टता मिलती है कि छात्र किस कौशल में माहिर हो रहे हैं और उन्हें कहां सुधार करने की आवश्यकता होती है।

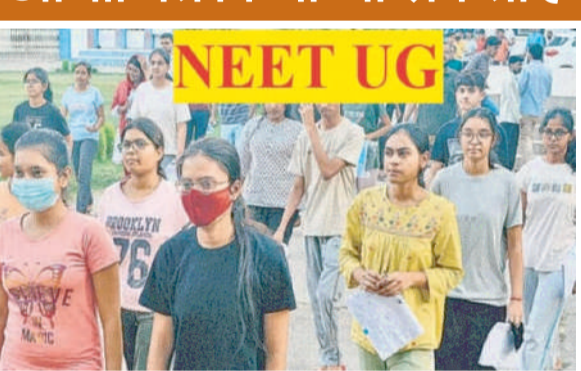
पूर्वाग्रह को कम करना: सीबीए पारंपरिक ग्रेड के बजाय मास्टरी के उद्देश्य मानदंडों पर ध्यान केंद्रित करके, एक अधिक निष्पक्ष मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में मदद करता है। संक्षेप में, सीबीए गणित साक्षरता विकसित करके छात्रों को बेहतर तैयार करता है - व्यावहारिक परिस्थितियों पर गणितीय ज्ञान लागू करने की क्षमता - जो 21वीं सदी में गणनात्मक कौशल रखने से कहीं अधिक मूल्यवान है।

### निष्कर्ष

योग्यता-आधारित मूल्यांकन गणित सिखाने और मापने के तरीके पर एक मौलिक पुनर्विचार का प्रतिनिधित्व करता है। यह परीक्षाओं की जगह लेने के बारे में नहीं है, बल्कि सफलता को पुनः परिभाषित करने के बारे में है - यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक छात्र तर्क, विश्लेषण और नवाचार के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त करे। गणित शिक्षा का भविष्य यह नहीं है कि छात्र क्या याद करते हैं, बल्कि वे जो समझते हैं उसके साथ क्या कर सकते हैं उसका आकलन करना।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, शैक्षिक स्तंभकार, प्रख्यात शिक्षाविद्, गली कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

## नीट युजी वर्ष में दो बार आयोजित किया जा सकता है



### विजय गर्ग

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एक प्रश्न का उत्तर 1 अगस्त को लोकसभा इसमें 115,900 एमबीबीएस हैं 780 मेडिकल सीटें देश में कॉलेज। एक नेशनल से अपडेट चिकित्सा आयोग पर 26 सितंबर, 2025 को सीटों की संख्या 809 मेडिकल कॉलेजों में 124,825। यह आने वाले वर्षों में और अधिक बढ़ने की उम्मीद है। इस तरह की संख्याओं के साथ कागज और पेंसिल मोड में राष्ट्रीय पाठ्य-क्रम-प्रवेश परीक्षा आयोजित करना एक हर्कुलियन कार्य है और कई चीजें गलत हो सकती हैं। बड़ी संख्या की आवश्यकता के अलावा केंद्र, कुछ पुरानी समस्याएं नकलीकरण, ड्रेस कोड उल्लंघन, कागज लीक और जल्द ही इस पर बातचीत कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षाओं पर स्विच करने की इच्छा जारी है और शिक्षा मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है विकल्प. उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, ऑनलाइन परीक्षाएं विभिन्न दिनों

और यहां तक कि एक दिन के भीतर आयोजित की जा सकती हैं, जिससे परेशानी मुक्त परीक्षा होगी। चूंकि केंद्रों की संख्या भी कम होगी, इसलिए पर्यवेक्षण करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता है और प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखना कम होगा। प्रश्नपत्रों का लीक भी नहीं होगा, क्योंकि उम्मीदवार एक ही प्रश्न पत्र का उत्तर नहीं देंगे। कंप्यूटर एक ही कठिनाई के स्तर पर वैकल्पिक पेपर उत्पन्न करेगा। एक और बड़ा लाभ यह है कि परीक्षा वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जा सकती है उन लोगों के लिए आसान बनाना जो आरएसटी परीक्षा से चुक जाते हैं या अपने स्कोर में सुधार करना चाहते हैं। परीक्षा के साथ, यह संभव नहीं था। लेकिन, यदि परीक्षा ऑनलाइन हो जाती है तो नीट युजी वर्ष में दो बार आयोजित की जा सकती है। सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, शैक्षिक स्तंभकार, प्रख्यात शिक्षाविद्, गली कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

## खेलों में व्यावसायिक दक्षता से मैनेज करें अपना कैरियर

विजय गर्ग

अगर आपको रुचि खेलों के व्यावसायिक पक्ष में है तो खेल प्रबंधन आपके सपनों का कैरियर हो सकता है। खेल प्रबंधन में कार्यरत पेशेवर खेल संगठनों, लीगों और आयोजनों की रीढ़ होते हैं। इनके लिए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में डिग्री या फिर अन्य पाठ्यक्रम उपयोगी हैं। इस क्षेत्र में कैरियर के अनेक अवसर हैं, जिनमें खेल संचालन, विपणन, इवेंट मैनेजमेंट, कोचिंग और खेल प्रबंधन कंसल्टिंग शामिल हैं। भारत में खेल अभूतपूर्व गति से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सही खिलाड़ियों की पहचान, चयन, प्रशिक्षण और खेल आयोजन को लेकर चुनौतियां भी बढ़ी हैं। वहीं अंतरराष्ट्रीय खेलों में भारत की बढ़ती भागीदारी ने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की मांग को बढ़ा दिया है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट खेलों के प्रति जुनून पर आधारित एक उज्वल कैरियर है। यह क्षेत्र प्रमुख खेल आयोजनों और संगठनों की योजना बनाने, व्यवस्थित करने और नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कौशल से जुड़ा है। खेल उद्योग के सुचारू संचालन में रुचि रखने वालों के लिए एक रोमांचक कैरियर है। खेलों के विकास के माहौल में कैरियर विकल्प के रूप में स्पोर्ट्स की उज्वल संभावनाएं हैं।

### स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्या है

खेल प्रबंधन तेजी से बढ़ रहा है और इसमें खेल संचालन, खेल विपणन, सुविधा प्रबंधन और एथलेटिक प्रशासन शामिल हैं। अगर आपको खेलों का व्यावसायिक पक्ष पसंद है तो खेल प्रबंधन आपके सपनों की नौकरी हो सकती है। खेल प्रबंधन में लगे लोग खेल संगठनों, लीगों और आयोजनों की रीढ़ होते हैं। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कौशल हैं - रणनीतिक योजना बनाना, धन का प्रबंधन करना, कार्यक्रमों का समन्वय करना और आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेना। खेल उद्योग तेजी से बदलता रहता है, इसलिए खेल प्रबंधन के पेशेवरों को नए रुझानों और तकनीकों के साथ अद्यतन रहना आवश्यक है।

### महत्वपूर्ण कार्य

टीम प्रबंधन: खिलाड़ियों की भर्ती, प्रशिक्षण, अनुबंध वार्ता और प्रदर्शन प्रबंधन सहित खेल टीमों के संचालन की देखरेख करना। इवेंट मैनेजमेंट: स्थानीय प्रतिযোগिताओं से लेकर अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों तक, खेल आयोजनों का आयोजन और प्रबंधन। इसमें लॉजिस्टिक्स, शेड्यूलिंग, टिकट बिक्री और इवेंट प्रबंधन शामिल हैं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से जुड़े प्रोफेशनल्स फिटनेस और बजट का प्रावधान कर इससे जुड़े ह्यूमन रिसोर्सेज और संबंधित लोगों का ध्यान रखते हैं। वे खेलों का आयोजन करने के साथ-साथ इवेंट्स और टीमों की मार्केटिंग जैसे महत्वपूर्ण काम भी करते हैं। उनके कार्यों में उपलब्ध सुविधाओं का दोहन तथा उसके लिए कार्यवाही करना, स्पोर्ट्स से जुड़ी योजना बनाना और आवश्यक निर्णय लेना भी शामिल है। इसके लिए आपको अपने संगठन को बेहतर और अधिक लाभदायक बनाने के नए



तरीके खोजने में कुशल होना चाहिए। सफल स्पोर्ट्स मैनेजर्स केवल प्रशासक नहीं होते बल्कि वे रणनीतिक विचारक होते हैं जो अपने संगठनों को संपन्न, टिकाऊ व्यवसायों में बदल सकते हैं। देश-विदेश में अवसर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में कैरियर के अनेक अवसर हैं, जिनमें खेल संचालन, विपणन, इवेंट मैनेजमेंट, कोचिंग और खेल प्रबंधन कंसल्टिंग शामिल हैं। इस क्षेत्र में सफलता के लिए रणनीतिक योजना, वित्तीय प्रबंधन और खेल उद्योग के रुझानों की जानकारी आवश्यक है। वे खेल गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाते हैं और राजस्व बढ़ाते हैं। ताकि उनके खेल संगठन और अधिक सफल और टिकाऊ बनें। खेल प्रबंधन का मतलब एक ऐसा सुसंगत और समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो खिलाड़ियों, प्रशंसकों और संगठनों को फलने-फूलने का अवसर दे। इस क्षेत्र में देश के साथ-साथ विदेशों में भी भरपूर कैरियर अवसर उपलब्ध हैं। खेल संगठनों को सफल बनाने के लिए हर भूमिका महत्वपूर्ण है। खेल संचालन इसका एक बड़ा हिस्सा है। यह खेल टीमों, लीगों या सुविधाओं के दैनिक संचालन से संबंधित है।

### जॉब और पारिश्रमिक

खेल संचालन प्रबंधक, खेल टीमों और लीगों के दैनिक कार्यों का प्रबंधन करते हैं। वे आयोजनों को सफल बनाने के लिए धन, कार्यक्रम और रसद का प्रबंधन करते हैं। कड़ी मेहनत करते हैं ताकि एथलीटों, प्रशिक्षकों और प्रशंसकों का समय अच्छा बीते। वहीं खेल सुविधा प्रबंधक, खेल स्थलों की देखभाल करते हैं। उन्हें सुरक्षित और सुचारू चलाने में योगदान देते हैं। तकनीक और सुरक्षा के अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं। आजकल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक कमाऊ कैरियर बन गया है, जिसकी प्रारंभिक सालाना आयु ही 25 लाख रुपये से आरंभ होती है। टाटा, रिलायंस और कॉर्पोरेट जगत के स्पोर्ट्स मैनेजर्स की आय तो करोड़ों रुपये में है।

### बदलावों के प्रति अनुकूलता

खेल प्रबंधकों को डेटा विश्लेषण को अपनाकर, नवीन विपणन रणनीतियां विकसित करके तथा हितधारकों के साथ मजबूत संबंध बनाकर इन प्रवृत्तियों के अनुकूल होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, खेल जगत में सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता पर बढ़ते जोर के कारण खेल प्रबंधकों को अपने निर्णयों के नैतिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर विचार करना आवश्यक हो गया है। खेल प्रबंधन और उनसे निपटने की क्षमता पर निर्भर करता है, साथ ही इस गतिशील और निरंतर बदलते उद्योग द्वारा प्रस्तुत अवसरों को अपनाने पर भी निर्भर करता है। प्रतिभाशाली और नवोन्मेषी खेल प्रबंधकों की हमेशा आवश्यकता रहेगी। कोई भी व्यक्ति एकल खेल प्रबंधन या बहु-खेल प्रबंधन उद्यम में सफल हो सकता है।

### कौशल और अनुभव

खेल संचालन और खेल सुविधा प्रबंधन में लगे लोगों को व्यावसायिक कौशल और खेल ज्ञान के संयोजन की आवश्यकता होती है। खेल प्रबंधन में शैक्षणिक कार्यक्रम छात्रों को व्यावहारिक अनुभव और शैक्षणिक ज्ञान प्रदान करके खेल उद्योग में विभिन्न भूमिकाओं के लिए तैयार करते हैं। उन्हें समस्या-समाधान, बार्गीकियों पर ध्यान देने और एक साथ कई काम करने में कुशल होना चाहिए। एथलेटिक प्रबंधन में कई लोगों के पास खेल प्रबंधन, व्यवसाय या सुविधा प्रबंधन में डिग्री होती है। अनुभव, प्रमाणपत्र और खेलों के प्रति प्रेम भी मददगार साबित होते हैं। इस क्षेत्र में कैरियर बनाने वालों को शारीरिक शिक्षा सहित किसी भी विषय में उपाधि प्राप्त करने के अलावा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में डिग्री हासिल करनी चाहिए।

### उपयोगी कोर्स

खेल उद्योग में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एजुकेशन का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे-जैसे खेल जगत अधिक जटिल, प्रतिस्पर्धी और वैश्वीकृत होता जा रहा है, वैसे-वैसे ऐसे योग्य पेशेवरों की मांग भी बढ़ रही है जिन्हें खेल के व्यवसाय, विपणन, संचालन और रणनीतिक पहलुओं को गहरी समझ हो। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स एक विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रम है जिसे भारत सरकार के साथ-साथ अन्य देशों के अपने निर्णयों के नैतिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर विचार करना आवश्यक हो गया है। खेल प्रबंधन और उनसे निपटने की क्षमता पर निर्भर करता है, साथ ही इस गतिशील और निरंतर बदलते उद्योग द्वारा प्रस्तुत अवसरों को अपनाने पर भी निर्भर करता है। प्रतिभाशाली और नवोन्मेषी खेल प्रबंधकों की हमेशा आवश्यकता रहेगी। कोई भी व्यक्ति एकल खेल प्रबंधन या बहु-खेल प्रबंधन उद्यम में सफल हो सकता है।

### महत्वपूर्ण संस्थान

खेल प्रबंधन के पाठ्यक्रम और कार्यक्रम इस क्षेत्र के लिए आवश्यक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। भारत में इस क्षेत्र में कई प्रतिष्ठित संस्थाएं व कॉलेज हैं जैसे - नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, पटियाला, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्यालियर, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज, तिरुवनंतपुरम (केरल), सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज, पुणे, तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, चेन्नई, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, दिल्ली, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, पुणे, हिमालयन माउंटनिंग एंड इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, गोवा।

### सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब



# बिहार में छठ के बाद 2 फेज में चुनाव 6 नतीजे 14 को और 11 नवंबर को वोटिंग

परिवहन विशेष न्यूज

बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर 2 फेज में वोटिंग होगी। मतदान 6 और 11 नवंबर को और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। चुनाव आयोग ने सोमवार शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। चुनाव के ऐलान से काउंटिंग तक की प्रक्रिया 40 दिन चलेगी। पहले फेज की वोटिंग छठ के 8 दिन बाद होगी। सभी राजनीतिक दलों ने वोटिंग की तारीखें दिवाली और छठ के बाद रखने की अपील की थी। बिहार में 40 साल बाद दो फेज में चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले 1985 में चुनाव 2 फेज में हुए थे। भाजपा और आरजेडी ने 2 फेज में चुनाव कराने की मांग की थी। जेडीयू ने एक फेज में चुनाव कराने को कहा था। पिछले चुनाव यानी 2020 में 3 फेज में 20 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच वोटिंग हुई थी। 10 नवंबर को नतीजे घोषित हुए थे। इससे पहले 2015 में 5 फेज में 12 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच वोटिंग और 8 नवंबर को नतीजे आए थे। राज्य में 243 सीटें हैं, जिनमें करीब 7.42 करोड़ वोट हैं। इनमें 100

## बिहार विधानसभा चुनाव 2025

**मतदान**

पहला चरण **6 नवंबर**

दूसरा चरण **11 नवंबर**

**परिणाम**

**14 नवंबर**

साल ऊपर के 14 हजार वोटर शामिल हैं। पोलिंग बूथ जाने में असमर्थ लोग फॉर्म 12 D भरकर घर से वोट डाल सकेंगे। राज्य में 14 लाख लोग पहली बार वोट डालेंगे। इस बार वोटर बूथ तक मोबाइल ले जा सकेंगे। चुनाव आयोग ने 7 राज्यों में विधानसभा सीटों पर उप चुनाव का ऐलान भी किया। जम्मू-कश्मीर में बडगाम और नागरोटा, राजस्थान में अंता, झारखंड में घाटसिला (ST), तेलंगाना की जुबली हिल्स, पंजाब की तरनतारन, मिजोरम की डम्मा और ओडिशा की नुआपाडा विधानसभा सीट शामिल हैं। यहां 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे।

# “जातीय समीकरण और सामाजिक न्याय – बिहार राजनीति की धुरी”



(डॉ. राजकुमार यादव के विश्लेषण पर आधारित विशेष रिपोर्ट)

जाति वर्ग	आबादी (%)	
प्रमुख राजनीतिक प्रभाव		
अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)	36%	
JDU, HAM, VIP		
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC – यादव, कुर्मी, कोइरी आदि)	27%	
R J D , JDU		
अनुसूचित जाति (SC)	19.65%	
LJP, BSP, RJD		
अनुसूचित जनजाति (ST)	1.68%	
सीमांचल / झारखंड सीमा क्षेत्र		
उच्च जातियाँ (ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ)	14%	
BJP, कांग्रेस		
मुस्लिम समुदाय	16%	
R J D , AIMIM, कांग्रेस		
कुल EBC + OBC आबादी = लगभग 63%		
यही वर्ग “निर्णायक मतदाता” कहलाता है।		
प्रमुख सामाजिक न्याय संबंधी मुद्दे		
विषय	मतदाताओं की चिंता	राजनीतिक रुख
रोजगार और आरक्षण	बेरोजगारी	
घटे, EBC/OBC को नौकरी में समान अवसर		
सभी दल आरक्षण की सीमा पर पुनर्विचार की बात		



कर रहे हैं

शिक्षा में अवसर गौंव-गौंव स्कूल, शिक्षक उपलब्धता “जन सुराज” व अन्य संगठन शिक्षा को राजनीतिक एजेंडा बना रहे

महिला और दलित अधिकार पंचायत व स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व R J D , JDU दोनों “महादलित” वोट पर ध्यान केंद्रित

जाति जनगणना आंकड़े को नीति में लागू करने की मांग RJD-JDU गठबंधन ने इसे राजनीतिक आधार बनाया

पलायन और विकास रोजगार की कमी के कारण युवाओं का पलायन भा ज पा “विकास बनाम जाति” नैरेटिव को आगे बढ़ा रही है

जातीय समीकरण के आधार पर वोट बैंक रणनीति (2025)

पार्टी मुख्य वोट बैंक रणनीतिक फोकस

RJD यादव + मुस्लिम जा ती य एकता और सामाजिक न्याय की नीति

JDU कुर्मी + EBC “सुशासन” और संतुलित विकास का दावा

BJP उच्च जाति + अति पिछड़े वर्गों का विभाजन जाति से ऊपर “राष्ट्रीय विकास” पर बल

कांग्रेस अल्पसंख्यक + शहरी वर्ग

सामाजिक समरसता और बेरोजगारी समाधान LJP /RLSP / छोटे दल द लित ,

पासवान, कोइरी प्रतिनिधित्व आधारित राजनीति

क्षेत्रवार जातीय प्रभाव (Regional Variation)

क्षेत्र प्रमुख जातियाँ राजनीतिक झुकाव

मिथिलांचल ब्राह्मण, कायस्थ, यादव मिश्रित – RJD और BJP दोनों का असर

मगध यादव, पासवान, कुर्मी RJD और JDU का टकराव

सीमांचल मुस्लिम, ओबीसी RJD, AIMIM का प्रभाव

भोजपुर-शाहाबाद भूमिहार, राजपूत, यादव

BJP, RJD दोनों सक्रिय

उत्तर बिहार EBC, दलित

JDU का परंपरागत प्रभाव क्षेत्र

डॉ. राजकुमार यादव का विश्लेषण

“बिहार की राजनीति आज भी सामाजिक न्याय और जातीय प्रतिनिधित्व की धुरी पर टिकी हुई है।

हालाँकि विकास, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे जरूर उभर रहे हैं, लेकिन जातीय अस्मिता अब भी वोट के मानस को दिशा देती है।”

— डॉ. राजकुमार यादव, राष्ट्रीय संयोजक - ओबीसी अधिकार मंच

# अमृतसर के मेयर जतिंदर सिंह भाटिया ने भगवान वाल्मीकि जी के प्रगट दिवस की तैयारियों का जायजा लिया

अमृतसर 6 अक्टूबर (साहिल बेरी)

नगर निगम के मेयर जतिंदर सिंह भाटिया और विधायक डॉ. अजय गुप्ता ने सोमवार को भगवान वाल्मीकि जी के प्रगट दिवस की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने शोभा यात्रा के मार्ग पर सफाई व्यवस्था में कोई कमी न छोड़ने के आदेश दिए। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम से कहा गया कि त्योहारों के मौसम में बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। ऐसे में निगम की टीम को सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए विशेष कदम उठाने पड़ेंगे। इसमें लोगों को भी इधर-उधर कूड़ा न फेंकने के लिए जागरूक किया जाए। इसके साथ ही, बाजारों और गलियों में कूड़े के ढेर न लगने दिए जाएं। उन्होंने कहा कि भगवान वाल्मीकि जी के प्रगट दिवस के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जानी है। ऐसे में



स्वास्थ्य विभाग की टीम शोभा यात्रा के मार्ग पर विशेष ध्यान दे। उन्होंने यह भी कहा कि शहर की सफाई-सफाई की जिम्मेदारी जल्द ही एक नई कंपनी को सौंपी जा रही है। इसके बाद, बैल टू बैल कूड़ा लिफ्टिंग सिस्टम पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। इसमें कूड़े से संबंधित शहरवासियों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा। इस



अवसर पर विधायक स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. किरण कुमार, चोफ सेनेटरी इंस्पेक्टर, सेनेटरी इंस्पेक्टर और कर्मचारी मौजूद थे।

# राज्यसभा में गुप्ता के साथ मेयर-विधायकों ने शहर के विकास को लेकर की चर्चा

अमृतसर 6 अक्टूबर (साहिल बेरी)

राज्यसभा में गुप्ता के साथ मेयर जतिंदर सिंह भाटिया और विधायकों ने मुलाकात की। जिसमें गुरुनगरी के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। मेयर जतिंदर सिंह भाटिया ने कहा कि आबादी बढ़ने के हिसाब से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों की क्षमता कम पड़ रही है। ऐसे में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता आबादी के हिसाब से बढ़नी चाहिए। इससे शहरवासियों को सीवरेज जाम की समस्या से राहत मिल सकेगी। शहर में पुरानी वाटर सप्लाई और



सीवरेज लाइनों को कई जगह से बदलने की जरूरत है। निगम अपने स्तर पर लगातार काम कर रहा है लेकिन इसके लिए ज्यादा फंड की जरूरत है। शहर में रोजाना लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, ऐसे में धार्मिक शहर

को स्पेशल फंड मिलने चाहिए। विधायकों ने भी शहर की जरूरतों को लेकर राज्यसभा में मेयर के सामने अपनी बात रखी। जिसपर गुप्ता ने केंद्र सरकार से पैसे दिलाने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर विधायक डा.

अजय गुप्ता, विधायक डा. इंद्रबीर सिंह निज्जर, विधायक डा. जसवीर सिंह, नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन कर्मजीत सिंह रिट्टू, जिला प्रधान प्रभवीर बराड़, नगर सुधार ट्रस्ट के मेबर मुखविंदर विरदी मौजूद रहे।

# सरायकेला एस पी लुनायत ने आदित्यपुर में पकड़ा चालीस लाख का ब्राउन शुगर

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड – झारखंड रांची। अफीम, डोडा, ब्राउन शुगर का अवैध कारोबार में नाम कंचा कर रहा सरायकेला खरसावा जिला के आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती में बड़ी कारवाई करते हुए करीब 40 लाख रुपये मूल्य की ब्राउन शुगर के साथ तीन तस्करो को गिरफ्तार किया है युवा एस पी मुकेश लुनायत। जिले में यह एक बड़ी जर्नी है। एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने सोमवार को जानकारी दी कि गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई थी। इस टीम ने छापेमारी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 207.91 ग्राम ब्राउन शुगर और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पकड़े गए तस्करो की पहचान शाहबाज खान, मोहम्मद समौर उर्फ मोहम्मद आमन और रफीकुल इस्लाम के रूप में हुई है। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसपी ने बताया कि यह कारवाई मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। उन्होंने कहा कि जिले में ब्राउन शुगर जैसी नशीली चीजों की बिक्री और तस्करी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और आगे भी इस तरह की कारवाई जारी रहेगी।



# झारखंड के घाटशिला समेत देश के आठ सीटों पर चुनाव 11 नवम्बर को, परिणाम 14 को

शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन घाटशिला विधायक असामयिक निधन के कारण चुनाव कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड – झारखंड जमशेदपुर, भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही आठ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। झारखंड की घाटशिला सीट पर उपचुनाव से जुड़ी तैयारियां भी जारी हैं। नोटिफिकेशन, नामिनेशन, नाम को वापस लेने, मतदान और रिजल्ट जैसे कार्यक्रम की पूरी सूची निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 20 अक्टूबर नामिनेशन फाइनल करने का आखिरी दिन होगा। स्कूटी के लिए 22 अक्टूबर का दिन रखा गया है। नाम वापस लेने की तारीख 24 अक्टूबर है। आठों जगह होने वाले उपचुनाव के लिए इन सब मामलों में तारीखें अलग-अलग हैं, लेकिन मतदान और चुनाव परिणाम के घोषित होने की तारीख समान है। 11 नवंबर को मतदान और 14 नवंबर को परिणाम सामने आएंगे। घाटशिला अनुसूचित जनजाति (एसटी आरक्षित) सीट है। यहां के सिटिंग विधायक और तत्कालीन मंत्री रामदास सोरेन के निधन के चलते उपचुनाव कराए जा रहे हैं। रामदास सोरेन का अगस्त 2025 में आकस्मिक निधन हो गया था। झारखंड के घाटशिला समेत आठ अन्य विधानसभा में जम्मू-कश्मीर की बुधगाम और नागरोटा, राजस्थान की आंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबली हिल्स, पंजाब की तरन तारन, मिजोरम की दंपा और ओडिशा की नोपादा शामिल हैं। इन सभी जगहों पर 11 नवंबर को मतदान होना है, जिसके परिणाम एक साथ 14 नवंबर को आएंगे।



# टीचर्स ऑफ बिहार द्वारा आयोजित “बाल सागर प्रतियोगिता” का परिणाम घोषित

## Teachers Of Bihar

### The Change Makers

# बाल सागर प्रतियोगिता

[www.teachersofbihar.org](http://www.teachersofbihar.org)

परिवहन विशेष न्यूज

पटना। श्रीमकालीन अवकाश के दौरान टीचर्स ऑफ बिहार ने शिक्षकों की रचनात्मकता और अभिव्यक्ति को मंच देने हेतु “बाल सागर प्रतियोगिता” का सफल आयोजन किया।

इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी शिक्षकों को चित्र देखकर बाल कथा लिखनी थी, जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी कल्पनाशक्ति, लेखन-कौशल और अभिव्यक्ति की क्षमता का परिचय दिया।

प्रतियोगिता का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 5) के विद्यार्थियों के लिए शिक्षाप्रद एवं रोचक कथाएँ तैयार करवाना था, जिससे बाल साहित्य लेखन के क्षेत्र में शिक्षकों की रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिल सके।

**मूल्यांकन के प्रमुख बिंदु रहे—**

- शोषक की उपयुक्तता
- सरल शब्द संयोजन
- चित्र आधारित कथानक
- नैतिक शिक्षा

इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों के शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी लेखन प्रतिभा का प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने शिक्षा जगत के विविध पहलुओं को अपनी लेखनी से जीवंत बनाया।

टीचर्स ऑफ बिहार के फाउंडर शिव कुमार एवं टेक्निकल टीम लीडर ई. शिवेंद्र प्रकाश सुमन ने संयुक्त रूप से कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य शिक्षकों की रचनात्मक ऊर्जा को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है, जहाँ वे अपने विचारों को समाज के साथ साझा कर सकें।

कार्यक्रम आयोजक कुमारी नीधि (राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित), एडिटर सुबोध कुमार द्विवेदी तथा आस्था दीपाली ने बताया कि प्रतियोगिता को शिक्षकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

यह सहभागिता इस बात का प्रमाण है कि शिक्षक केवल शिक्षण कार्य तक सीमित नहीं हैं, बल्कि साहित्य, अभिव्यक्ति और सृजनशीलता में भी अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं।

प्रदेश प्रवक्ता रंजेश कुमार एवं प्रदेश मीडिया संयोजक मृत्युंजय कुमार ने संयुक्त रूप से कहा कि इस प्रकार की पहल न केवल शिक्षकों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर देती है, बल्कि शिक्षा जगत में एक सकारात्मक और रचनात्मक माहौल भी तैयार करती है।

विजेता प्रतिभागी:-

प्रथम स्थान – राम किशोर पाठक, प्रा. वि. भेड़हरिया इंग्लिश, पालीगंज, पटना

द्वितीय स्थान – श्वेता साक्षी, खगड़िया, बिहार

तृतीय स्थान – लवली कुमारी, उ. म. वि. अनुपनगर, बारसाई, कटिहार

चतुर्थ स्थान – राजन कुमार, रा. प्रा. वि. बैरिया, गौनाहा, पश्चिम चम्पारण

चतुर्थ स्थान – भोला झा

पंचम स्थान – नेहा कुमारी, रा. स. हरावत राज उ. म. वि., गणपतगंज, राधोपुर, सुपौल

पंचम स्थान – शैलेंद्र कुमार, उ. म. वि. औसानी, बगहा-2, पश्चिम चम्पारण

आयोजक कुमारी निधि (प्राथमिक विद्यालय बिरनाबाड़ी, पोठिया, किशनगंज) ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य शिक्षकों में बाल साहित्य लेखन के प्रति रुचि विकसित करना और शिक्षण के साथ-साथ रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना था।

टीचर्स ऑफ बिहार परिवार ने सभी विजेताओं एवं प्रतिभागियों को बधाई दी और सभी को डिजिटल प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

# श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व को समर्पित जिला प्रशासनिक परिसर में कराया गया श्री सुखमनी साहिब का पाठ

अमृतसर, 6 अक्टूबर (साहिल बेरी)

श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आज जिला प्रशासनिक परिसर, अमृतसर में श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव से आयोजित किया गया। पाठ उपरांत रागी सिंंहों द्वारा इलाही बाणी का मधुर कीर्तन किया गया, जिससे पूरा वातावरण गुरुबाणी के स्वर से गूँज उठा।

इस अवसर पर संगत को गुरु का अटूट लंगर भी वितरित किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अनेक अधिकारीगण एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर श्रीमती साक्षी साहनी, एस.एस.पी. (देहाती) श्री मनिंदर सिंह, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर श्री रोहित गुप्ता, श्रीमती अमनदीप कौर, एस.डी.एम. श्री गुरसिमरन सिंह, एस.डी.एम. श्री मनकवल सिंह चाहल, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर नगर निगम श्री सुरिंदर कुमार, ज्वाइंट कमिश्नर नगर निगम श्री जय इंद्र सिंह, जिला माल अधिकारी श्री नवकीरत सिंह रंधावा, डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के सुपरिटेण्डेंट श्री अनील कुमार, श्री



हरपाल सिंह तथा जिला नाजर श्री सुखविंदर सिंह ने गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान सभी ने मिलकर गुरु के उपदेशों पर चलने और समाज में सेवा, समर्पण तथा भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।